CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Internal Security Problem with referene to the State of Jammu and Kashmir-*Contd*

उपसभापति : अहलुवालिया जी आप के लिए पांच मिनट हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार): मैडम, अगर 7 मिनट के 45 मिनट हो सकते हैं तो 5 मिनट के 35 तो हो ही सकते हैं ।

उपसभापति : वह समय चेयरमैंन साहब ने दिया था । वह बहुत जेनरस हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैडम, जेनरस की बात नहीं है ।

But generosity does not come for a particular purpose or for a particular person. It should be uniform.

उपसभापति : अहलुवालिया जी आप दूसरे समय पर जरूर बोलिए । 10 मिनट नहीं, 20-25 मिनट बोलिए । मगर समस्या यह है कि बहुत से नाम है और कालिंग अटेंशन में हम लोग निर्णय लेतें हैं कि हम इसको एक घंटे में खत्म करेंगे which is not possible with all the names. Sometimes we take impracticable decisions. I shall try to be practical.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I fully agree with you. But this clause should be applicable to each and every speaker . इस केस को भूल जाइये । आप आज के दिन भूल जाइये । कल से इसको लागू करेंगी तो अच्छा रहेगा ।

उपसभापति : आप बोलना शुरू करिए और यह ध्यान रखिए की आप भी इस हाउस के मेमबर हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ठीक है । उपसभापति महोदया, आज हम जम्मू एंड कश्मीर पर ध्यानाकर्षण विषय पर बात कर रहें हैं । जम्मू एंड कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग हैं । जब से भारत बना तब से वह हमारा अभिन्न अंग बना और जब तक भारत रहेगा वह हमारा अभिन्न अंग रहेगा । इस सोच को लेकर के अगर हम चलें तो बहुत सारे वाद-विवाद यूं ही समाप्त हो जाएंगे ।

मेरे पर्वू वक्ता ने इस प्रस्ताव को सामने रखते हुए जो कुछ कहा है और उनके पुरे वक्तव्य का अगर मैं विश्लेषण करूं तो मुझे याद आता है कि कोई इतिहास का छात्र इतिहास

के कुछ पन्नों को भूल जाता है और सिर्फ कुछ पन्नों को ही पढ़ता है और उसी के द्वारा एक नया इतिहास गढ़ना चाहता है । मैं पुरानी बात करूं तो इसकी शुरूआत 1947 से होती है जब तथाकथित पाकिस्तानी समर्थित कबालियों के कश्मीर पर हमला किया और उन तथाकथित कबालियों को पाकिस्तान का पूरा समर्थन उसी तरह से हासिल था जिस तरह से आज वहां जो आंतकवाद फैलाया जा रहा है उनको कर रहें हैं । दुर्भाग्य की बात है कि मौके के नेताओं ने उस वक्त पाक आक्युपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर की आख्या भी दी जिसको लेकर यूनाईटेड नेशन्स की सिक्योरिटी काउन्सिल में कृष्णा मेनन की मैराथन स्पीजिच हैं । उन्होनें जो कहा उसमें उन्होनें खुद के प्रधान मंत्री के वक्तव्य प्रश्नचिह्न लगाया था । शुरूआत कश्मीर की कहां से करूं ? कश्मीर एक नासूर बन गया है । इस नासुर कश्मीर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की प्राब्लम को मैं कह रहा हूं । आप तो चौंकें हैं । आप तो चौकैंगे, बहुत कुछ में चौकेंगे । कश्मीर का प्राब्लम एक नासूर बन चुका है और यह नासूर क्यों बना ? उसके पीछे कौन-कौन से इतिहास के पन्ने मैं खोलूं और कौन-कौन से पन्ने खोलकर मैं बताऊं कि हमारे यहां इस सदन में जो उस इतिहास से जुडे हुए हैं वह भी माननीय सदस्य हैं, वे वहां के सदरे-रियासत रह चुके हैं । उस इतिहास को अगर मैं जोड़ने लगूं तो सवाल आता है कि शेख अबदुल्ला को क्यों गिरफ्मार किया गया था? सदरे-रियासत के हुक्म पर क्यों गिरफ्तार किया गया था ? क्या कारण थे ? क्या वजह बनी थी ? कौन-सी मुसीबत आन पड़ी थी ? क्या वह हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहें थे या पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करने जा रहे थे जो हमारे हक में नहीं था या हमारी संस्कृति और सभ्यता पर एक धब्बा बनता या हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता? मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि अब बहुत सारी चीजें उछल रहीं हैं । हम कई चीजें सदन में ऐसी बोल देतें हैं जो हो सकता है कि हमारे दिल की भड़ास निकालने के लिए और दो दिन अखबारों में अपना नाम छापने के लिए अच्छी हो सकती हो किंतु बाद में वही बातें घूम-फिरकर पाकिस्तन के टी.वी. और पाकिस्तानी रेडियो के लिए प्रचार सामग्री का कारण बन जाती है, जिनको पढ़कर सारी दुनिया के लोग किस तरह से हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान के लोगों को शक और शुबहा की नजर से देखने लगते हैं, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते और उसके बारे में हम भूल जातें हैं । महोदया, जम्मू-कश्मीर की बहुत लम्बी कहानी हैं । जम्मू-कश्मीर की इस लम्बी कहानी और लम्बे दौर में मैं अपने पूर्व वक्ता जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ कश्मीर के दौर पर भी गया था उन्होनें कहा कि क्रॉस फायरिंग में लोग मारे जातें हैं । उस समय इनकी हुकूमत थी । जनाब गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर थे । मैं उनके साथ गया था। बारामुल्ला में पूरी वैली में स्ट्राइक डिक्लेयर हो गयी । उस समय कांग्रेस का राज था, पूरी वैली में स्ट्राइक डिक्लेयर हो गयी

थी । कोई भी डैलीगेशन जिनको हम मिलना चाहते थे और जिनसे जाकर कोई बात करके हम वहां की मुसीबतों को समझना चाहते थे...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचंद मीणा (**राजस्थान**): महोदया, अहलुवालिया जी पुराने इतिहास की बात कर रहें हैं, हम जम्मू-कश्मीर की समस्या के बारे में बात कर रहें हैं । पुरोन इतिहास में हम किसके साथ थे, कौन सी गर्वनमेंट थी, इस बात को कहने की क्या जरूरत हैं ?

उपसभापति : आप क्यों बोल रहें हैं, क्या आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहें हैं ?

श्री मूलचंद मीणा : जी, यही मैं कह रहा हूं ।

उपसभापति: इसमें कोई प्वाइंट आफॅ ऑर्डर नहीं हैं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सवा बारह बजे से एक बजे तक आप कहां थे ? ...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचंद मीणा : अहलुवालिया जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा विषय पर ही बोलें, इतिहास की ओर जाएंगे तो बहुत लम्बा इतिहास है, फिर तो दो-तीन घंटे डिस्कशन होती रहेगी । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वह तो चलेगी ही । इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा । इतिहास तो आपने हमें पढ़ाया है । ...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचंद मीणा : जम्मू-कश्मीर की समस्या सुलझाने की बात हो रही है या पुराने इतिहास की बात हो रही है ? ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार (**गुजरात**): अहलुवालिया जी, इतिहास के उस पन्ने को भी याद करो जब यहां बैठकर बोलते थे ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ठीक है । ...(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY(West Bengal): Madam, we have taken a decision that this side will speak for seven minutes and that side will speak for five minutes... *(Interruptions)*... He has just now started narrating the history. History will go on. I draw your attention to this. That is all... *(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (**उत्तर प्रदेश**) **:** पहले आप क्यों नहीं बोले ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down ...*(Interruptions)*...

Please take your seat... *(Interruptions)*... The thing is, I am concerned with the time of the House. If any part of his speech is against the rules of the House, I will stop him. But, I will only request him that he also keep his eyes on the watch.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, I am wearing a wrist-watch and I can see the wall clock as well.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Very good.

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is correct. But the earlier speaker was also wearing a wrist-watch and the wall clock was also there. The wall clock was just not hung.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. But, still, you will have to confine yourself to the time allotted to you... *(Interruptions)* ...You are a very disciplined Member.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, if you go through the record from 12.20 pm to 12.55 pm, you will know that History was taught to us. I am just trying to remind them as to what part of History they were reading and what the other part of the history says.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Go ahead.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं कह रहा था कि मेरे साथ पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब भी थे। हम लोग बारामुल्ला में गये जहां हमें एक जिले की मीटिंग बुलाकर सारे अफसरों से ब्रीफिंग लेनी थी। वहां कुछ ऐसी घटना घटी तो एक सवाल आया-सपलीमेंटरी सवाल पूछने की आदत पार्लियामेंट में है, वहां भी पूछ लिया गया- सवाल था कि दो करोड़ रूपये कंपनसेशन में उन लोगों को देने थे जो लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गये थे। महोदया, क्रॉस फायरिंग में मरने वाले एक आदमी के परिवार को एक लाख रूपये दिये जातें हैं। दो करोड़ का मतलब है कि दो सौ आदमी क्रॉस फायरिंग में मारे गये और वह भी सिर्फ बारामुल्ला जिले में और उसमें भी जो ज्यादा संख्या थी, वह सौहपुर के इलाके की थी। मैनें सिर्फ इतना सवाल किया कि मैं सौहपुर जाना चाहता हूं। मैं उन अफसरान का और उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होनें इस बात का विरोध किया और कहा कि आप सौहपुर नहीं जा सकते। मैनें कहा कि मैं जाकर देखना चाहता हूं और वहां के लोगों के दुख-दर्द, उनकी तकलीफ को समझना चाहता हूं, मुझे जाने दिया जाए। जब सौहपुर से माइग्रेशन शुरू हुआ और जब सौहापुर में क्रॉस फायरिंग में लोग मारे जा रहे थे, यह उस

समय की बात है। सडनली एक अफसर जो असिस्टेंट कमिश्नर या एडीश्नल कमिश्नर था डिस्ट्रिक्ट का, वह हिस्टीरिकल हो गया और बहुत जोर-जोर से बोलने लगा कि यहां सारी बातें आपको पता नहीं लगेंगी। और ये लोग नहीं बताएंगे, मैं बता सकता हूं। मैं बता सकता हूं किंतु अगर मैं बताऊंगा तो मेरी जान भी खतरे में आ जाएगी। वह जान खतरे में ऐसी आएगी कि मैं शायद कल की सुबह नहीं देख सकूंगा या आज का डूबता सूरज नहीं देख सकूंगा। मैनें गुलाम नबी आज़ाद साहब से गुजारिश की कि यह तो बड़ा अन्याय है और इस अफसरों को बुला कर अलग-अलग बात करें। इसके लिए मुझे पूरी तरह से याद है कि उन्होनें क्या-क्या बताया और क्या-क्या कहा।

शुरूआत आज की नहीं है महोदया, शुरूआत तो उस दिन से हो गई थी जब गुलाम नबी आजाद साहब के पड़ोस के गांव के मकबूल बट्ट साहब गिरफ्तार हुए थे। यह वाकया 1983 और 1984 का है। जब मकबूल बट्ट साहब को सजाए मौत दी गई तो दबाब चारों तरफ से बढ़ गया। उसके कारण हमारे एक डिप्टी हाई कमिश्नर युनाइटेड किंगडम के, रविन्दर कुमार महात्रे की किडनैपिंग हुई। कश्मीरी मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान की मदद से वहां किडनैपिंग की और वहां उसे मारकर चौराहे पर डाल दिया गया। तो महोदया, यह शुरूआत की बात है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि यह जो प्रॉब्लम है,यह एक नासूर बन चुकी है। इसका इलाज हमको बैठकर ढूंढना है और हम सबको बैठकर ढूंढना है। इस इलाज को ढूंढते हुए अगर हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो शायद हम कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे, हम भटक जाएंगे।

महोदया, आखिर आज ये चाहते क्या है ? मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका हेडिंग है- "Terrorism and Subversion in Jammu and Kashmir State of India by Pakistan trained Militants." यह बयान है अमानुल्ला खान का जो चेयरमैन हैं पाकिस्तानी बेस्ड जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के। उन्होनें बड़े फख़्र से कहा –

"In December 1989, at Rawalpindi, Amanullah Khan, Chairman of the Pak-based Jammu and Kashmir Liberation Front, announced that subvertives would wage on 18 month-long campaign of terror including hijacking, killings and kidnappings. He want on to say that the front's underground guerilla force operating in J&K had been given guideline: Don't touch our own people, but hit Indian property, including airlines, post-offices, and public buildings".

यह यहां पर समाप्त नहीं होता है। आगे कहा गया है-

"This is not a new development. It has been going on since 1947, and the end of Bangladesh war. The cadets in Pakistan Military Academy at Kakur swear an oath daily that one day they will avenge Bangladesh."

However, it was General Zia-u-Haq who really gave substance and motive force to this plan. At a top level meeting in April 1988, attended by selected corps commanders and top ISI officers, the General made a statement, as reported in IDR of Jury 1989. He said:

"Gentlemen, I have spoken on this subject at length before. Therefore, I will leave out details. As you know, due to our preoccupation in Afghanistan in the service of Islam, I have not been able to put these plans before you earlier. Let there be no mistake, however, that our aim remains quite clear and firm, the liberation of the Kashmir valley. Our Muslim Kashmiri brothers cannot be allowed to stay with India for any length of time now. In the past, we had opted for hamhanded military options and, therefore, failed. As have mentioned before, we will now keep our military option for the last moment as a *coup de grace* if and when necessary".

महोदया, यही नहीं उन्होनें जो अपनी कांस्पीरेसी रची, उसमें यह भी कहा – "Here we must adopt those methods of combat which the Kashmiri mind can grasp and cope with. In other words, a coordinated use of moral and physical means, other than military operations, which will destroy the will of enemy, damage his political capacity and expose him to the world as an oppressor. This aim, gentlemen, shall be achieved. उन्हानें फर्स्ट फेज में कहा- In the first phase which may, if necessary, last a couple of years, we will assist our Kashmiri brothers in getting hold of the border status." ... *(Interruptions)...*

श्री खान गुफ़रान खान आज़मी (**उत्तर प्रदेश**)**:** हम अहलुवालिया जी से कह रहे हैं कि आप क्यों पढ़ रहें हैं, आप जो पढ़ रहें हैं, इसको यहां पढ़कर क्रेडिबिलिटी रहें हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं आपको बता रहा हूं कि यह डिज़ाइन ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए तभी समझ आएगा । ...(**व्यवधान**)... आप तो कह रहें हों अभी शुरू हुआ है ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : हमें इससे ज्यादा मालूम हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप सुन लीजिए ।...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : आप क्या बताना चाह रहें हैं ? ...(**व्यवधान**)... जो आदमी पढ़ना नहीं चाहता उसको आप पढ़कर सुना रहें हैं ...(**व्यवधान**)... हाऊस के अंदर पढ़कर आप इससे क्रेडिबिलिटी लेना चाहतें है ? ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : दस मिनट से तो आप बुक से पढ़ रहें हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I am on a point of order. When we adjourned for lunch, it was decided that with the efforts of all the hon. Members, two Bills should be passed today. Now, it is the responsibility of the Treasury Benches to get these Bills passed. We can wait up to 7-8 o'clock. But, if they have the will that they can have their own time, then it is not binding on us to sit up to 9 o'clock. The Treasury Benches should show some responsibility. ... *(Interruptions)*...During the Calling Attention Motion on "Sankhya Vahini", time and again, we have been told that only questions have to be put. The points have to be put in the form of questions to the Minister....*(Interruptions)*...This is not the way. We are not going to sit like this. ...*(Interruptions)*...*We* are not going to sit after 8 o'clock.

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" : जब पचास मिनट बोला गया तब आपत्ति नहीं हुई । ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : I do not mind. You can go on speaking for the whole hour. But we will not sit beyond 8 o'clock. ... *(Interruptions)*... You can continue. We have no objection. Let him speak. आठ बजे के बाद नहीं बैठेंगे । ...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय : हम आठ बजे के बाद नहीं बैठेंगे । ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Let all the speakers speak, but the Treasury Benches should not insist on us to sit beyond 8 o'clock.

श्री हंसराज भारद्वाज(मध्य प्रदेश): अहलुवालिया जी, आप अपनी बात बोलें । ...(**व्यवधान**)... You are such a senior Member. Why are you bringing Amanulla Khan on our records?

SHRI S.S. AHLUWALIA : It is part of a conspiracy and it is already in the record. ... *(Interruptions)*...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: This is insult to the House. ... *(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA I have said that it is already on the record because, during your time, it was raised in this House. ... *(Interruptions)*...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: I am only suggesting to you something, in your interest. Why are you bringing in Amanulla Khan? We do not know this fellow, but you are giving credibility by reading from the book. It is for your Government to say. We do not have many differences on Kashmir issue. ... *(Interruptions)*...

SHRI *S.S.* AHLUWALIA: Today, you can say that you do not know this man. You have forgotten that your Minister and your Government have d iscussed and negotiated with them. ... *(Interruptions)*...

SHRI HAN, SRAJ BHARDWAJ : I am not a person like you who says, "My Ministry, your Ministry, etc." It is a question of the country. Yesterday, you wer e with us. But now you are having a different philosophy.

THE DEPUT Y CHAIRMAN : Let us not go into any discussion. The Home Minister w ill reply to whatever the Members are raising in this House. He is competent enough to reply. I have gone through the record. Yes; Mr. Ghulam Nabi Azad did take 45 minutes. He should have taken 25 minutes. As the initiator of the debate, we always give that much time to the Member. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA According to the rule book, it is seven minutes for the initiator and the rest of me people can get five minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN I am talking about conventions. So, when we are talking about conventions, generally, the initiator takes more time. Anyway, I am giving you enough time. Please try to speak within that time and conclude.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदया, मैं डाक्यूमेंट पढ़कर बताना चाहता हूं …(**व्यवधान**)…

THE DEPUTY CHAIRMAN : Somebody's telephone is ringing. If anybody's telephone rings in the House, I am going to confiscate it. Please go out and speak in the lobby. We must abide by the rules which we have made. Yesterday, I heard a ring from that side; today it is coming from this side. Let us have some discipline in the House.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदय, पाकिस्तान का षडयंत्र सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर इधर भिजवाने का ही नहीं है। उन्होनें इस षडयंत्र के तहत "ऑपरेशन टोपेक" के तहत कहा था कि हम वहां पर, कश्मीर में राजनैतिक नेताओं को, राजनैतिक बल भी दिलवांए, समय पर उसका प्रयोग भी करें और अपने काम में उनको मदद भी लें। मैं यही बात कहना चाहता था और यह हमारे सामने आई भी है। चरारे-शरीफ की घटना क्यों घटी ? हजरत बल में क्या हुआ ? हजरत बल में जो लोग पकड़े गए वे कौन थे ? किन देशों के थे ? क्या आज के अफगानिस्तान, सुडान या तालिबान के लोग हैं ? नहीं, उस वक्त भी यही लोग थे। और यह इन चीजों से जाहिर होता है। जिया-उल-हक ने कहा था कि हम अभी मशगूल हैं अफगानिस्तान की लडाई में, वहां की जंग में, ट्रेनिंग देकर वहां टेरेरिस्ट भेजे जा रहें थे। जब वहां से फ्री हुए तो यहां भेज दिए। लेकिन यह काम चलता रहा, निंरतर चलता रहा। महोदया, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जब भी कभी मौका लगा हमने कोई न कोई रास्ता निकालकर, वहां जाकर पहल की। चाहे वे नेहरू जी हों इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, सबने जाकर पहल की और उसे सोल्व किया। मैं समझता हूं कि 1947 के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के सरकारी अफसरानों में बहुत सारे कश्मीरी अफसर थे जो उच्च पदों पर पदासीन थे। यहां तक कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी कश्मीरी थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा जख्म, एक छोटी सी फुंसी किस तरह नासूर बनकर उभरी, यह देखने लायक है। महोदया, यह बात सही है जो गुलाम नबी जी ने कही कि यह डिच एंड डेविल का रिश्ता है। परंतु यह डिच एंड डेविल का रिशता एक दिन में नहीं बना है। यह डिच एंड डेविल का रिश्ता उसी दिन बन गया था जब सौहुपर की घटना हुई थी। जब आंतकवादी घर पर आये, खाना खिलाया गया, दूसरे दिन आकर आर्मी पकड़कर ले गई। जब आर्मी सुबह आई, जिस-जिस के घर गई, दूसरे दिन उनके सारे के सारे मैम्बर्स को आतंकवादी उठाकर ले गए। हम प्रोटेस्ट नहीं कर सके। हम यह दोष सरकारों को न दें। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो चक्रांत पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बैठकर रचा जा रहा है, हमारे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ उसके बारे में हमारी सोच क्या है ? हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं ? यह बात सही है कि कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो छह महीने बर्फ से ढका रहता है, छह महीने लोग काम करते हैं, मेहनत करके रोटी कमाते हैं और छह महीने बैठकर खाते हैं। छह महीने बैठकर कशीदें का काम करते हैं। छह

महीने का सरअंजाम उन्हें छह महीने के लिए जमा करके रखना पड़ता है, रसद जमा करके रखनी पड़ती है । वैसे हालातों में उन्हें जिन चीजों की जरूरत थी , कम्युनिकेशन की, सड़क की, टेलीफोन की, रेल लाइन पहुंचाने की, हवाई जहाज तथा हैलीकॉप्टर सर्विस की, ये सारी अभी तक क्यों नहीं पहुंच सकी ? इसका क्या कारण है ? हमने क्यों यह मान लिया कि साहब, शुरू से हमारी एक कमी थी? कहतें हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब किसी राज्य से खड़े होते हैं तो उस राज्य में खुशहाली आती है पर मुझे इस बात का जवाब कांग्रेस में रहतें हुए आज तक नहीं मिला कि पंडित जवाहर लाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे फिर भी उन्होनें कभी ऐसी सोच क्यों नहीं बनाई कि कश्मीर से लोक सभा का चुनाव लड़े । हो सकता है कि अगर कश्मीर से पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती तो शायद आज जो कश्मीर में प्राब्लम है वह नहीं होती ।

श्री राजू परमार : आज बोल रहे हो । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस में रहकर भी सोचता रहा । ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : आज बोल रहें हो आप ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : और तो और हमारे गुलाम नबी भाई भी, अगर वे वहां से चुनाव लड़ लेते —लेकिन वह भी महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र से पहली बार राज्य सभा में आए । ...(**व्यवधान**)... मैं तो बंगाल में पैदा हुआ हूं और बिहार में रहता हूं । दिखने में सिख जरूर हूं ...(**व्यवधान**)... मेरा देश तो स्यालकोट पाकिस्तान में चला गया और स्यालकोट से किसी दिन मैं चुनाव लड़ लूंगा । ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति महोदय, आज लश्करे तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसी ही कितनी संस्थायें हैं जो सरे आम जन्म ले रही है । उनकी आखिर कौन मदद कर रहा है ? किस से मदद लेकर ये आज हमारे देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं ? यह वही डिजायन काम कर रहा है जिस तरह से हमने अपने सिख भाइयों को अफगानिस्तान में देखा । अफगानिस्तान का काबुली वाला सारी दुनिया वालों को कर्ज देता है पर अफगानिस्तान का काबुल एक ऐसा शहर है जहां सिख काबुलियों को कर्ज दिया करता था । पर जिस दिन तालेबान का राज आया तो उन्होनें सबसे पहले गैर मुस्लिम जमात को वहां से निकाल बाहर किया और आज जो घटनायें घट रही हैं, सौहपुर की घटना हुई, बारामूला में घटनायें हुई, अनन्तनाग में घटनायें हुई, तब हमारे गुलाम नबी आजाद साहब दौरे पर थे । हमारे दूसरे मित्र भी मंत्री के रूप में दौरे पर जाते रहे । आप तो गांवों में, देहातों में घूम लेते थे लेकिन दूसरे मंत्री महोदय

को अगर चश्मेशाही से फुर्सत मिल जाती तो कुछ काम होता । यह चश्मेशाही एक ऐसी जगह है जहां बैठकर ही सारे फैसले हो जाते हैं । चश्मेशाही एक ऐसी जगह है जो हर तरह से बची हुई है । ...(**व्यवधान**)...

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार) : घर का भेदी लंका ढाए ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदय...

उपसभापति : आप जरा चश्मेशाही से बाहर आयें तो मैं दूसरों को बुलाऊं ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मेरा कहना है कि इन घटनाओं के बाद वहां हिंदु ब्राह्मण जितने थे वह माइग्रेट कर गए हैं । इस बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी तरह से कहा है । इसके लिए कौन कसूरवार है, किसकी गलती हे? अभी इन्होनें गिनाया कि शेल गिरे थे । तो क्या मेरे पूर्व वक्ता को नहीं मालूम कि हमारे गवर्नर राजभवन छोड़कर मिलेटरी कन्टोनेंट में रह रहें थे, यह किस जमाने की बात है ? इसलिए मैं कहता हूं कि जमाना ना गिनायें । अब एक षड़यंत्र हो रहा है और वह षडयंत्र यह है कि गैर-मुसलमान ज़मात अगर कश्मीर वेली में कोई रह गई है तो वह सिखों की है । उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है । पर ये आज के सिख नहीं हैं, ये सिख उस वक्त के हैं जब हमारा मटन, अनन्तनाग के पास एक जगह मटन कहलाती है, जिस तरह से लोग प्रयाग जातें हैं,संगम में जातें हैं, वैसे ही मटन मे लोग जाया करते थे । यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान था । लेकिन आज मटन में कोई अपने पूर्वजों की पूजा-अर्चना या पिंड-दान करने की सोच भी नहीं सकता । यह उसके लिए ख्वाब हैं, सपना है । उन्हें निकाला । तब सिखों को निकालने के लिए छत्तीसिंहपुरा में जो घटना घटी है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं । मैं वहां पर तनी बार गया था । मैने जब उन लोगों से सवाल किये तो एक महिला कहने लगी अहलुवालिया जी हम किस पर विश्वास करें । याकूब नाम का नाम ग्वाला जो रोज़ दूध देता था, जब वह आंतवादियों का हिस्सा बन के यहां आया और हमारे परिवार के नौजवान सदस्यों को गोलियो से भून कर चला गया तो हम किस पर विश्वास करें ? यह जो मुंह को खून लग गया है वहां के लोगों को,उनका यह चक्रात है जिस तरह से तालिबान ने उस इलाके से गैरमुसलमानों को निकाल दिया है, कश्मीर के इलाके से गैर मुसलमान को निकाल देना चाहते हैं । महोदया, हो सकता है इस सदन के बहुत सारे सदस्य कारगिल गये होंगे और उन्होनें कारगिल में जा कर देखा होगा । मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हैं कि मैं वहां सात दिन और सात रातें रहा । कारगिल की ९९.९ फीसदी पापुलेशन शिया है, रोते कलपते हैं, कहतें हैं कि पाकिस्तान से जितनी शैलिंग होती है, वह सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम सुन्नी नहीं हैं, मुसलमान हम भी हैं । खतरा कश्मीर की सिख पापुलेशन को है और पापुलेशन को भी बना हुआ है । ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : अब शिया सुन्नी का झगड़ा करवाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री हंसराज भारद्वाजः गवर्नमेंट किस लिए है, उसको रोको। ...(**व्यवधान**)... भाषण दे रहें हैं ...(**व्यवधान**)...

धम्मा विरियो श्रद्धेय (बिहार): कारगिल में बुद्धिस्ट भी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : कारगिल में बुद्धिस्ट नहीं है। आप जहां पर हैं, मुझे मालूम हैं। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ प्वांइट 10 परसेंट हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : यह जानना इतना नाजुक मसला है जिस पर अहलुवालिया जी बोल रहें हैं। इतने संमय के साथ कहना बोलना है कि यहां से बाहर जो चीज़ जाए उससे एकता बनी रहे न कि नफरत फैले। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ।...(**व्यवधान**)... मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जो असली मुद्दा है, उस पर बात करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : किस को खतरा है, वह बता रहा हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : टाइम का भी कुछ ख्याल करना चाहिए । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : 50 साल से एकता की बात कर रहें थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी **:** अब आप ऐसी जगह पहुंच गये हैं जहां एकता की सोच आपको नहीं आएगी। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : अहुवालिया जी अब ज़रा...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं राऊंड-अप कर रहा हूं।

उपसभापति : राऊंड-अप कर लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : वाइंउ-अप हो रहा है या राऊंड-अप हो रहा है ? ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : कह रहे हैं कि राऊंड-अप कर रहें हैं। ...(**व्यवधान**)... अच्छा राऊंड-अप करिये...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैडम ने परमिट किया है, राऊंड-अप कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी (**मध्य प्रदेश**): मैडम, फारसी में कहा जाता है तुखम तासीर, सोबते असर। इसलिए वाइंड-अप के बजाय राऊंड-अप कहना शुरू कर दिया है। यह सब कंपनी का असर है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सविता शारदा (**गुजरात**): यह मामला इतना सीरियस है, इसकों हंसी में नहीं उड़ाया जाना चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी : यह विषय इतना गंभीर है, इस पर गंभीरता से बोला जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैडम, यह बोलते रहेंगे तो मैं भी बोलता रहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is a very serious matter.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, instead of referring to the history and instead of creating a problem, let him suggest as to how this problem can be solved.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदया ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : अहलुवालिया जी, आपने काफी समय ले लिया है।...(**व्यवधान**)... Please have order in the House. अहलुवालिया जी, आपने अपने समय से ज्यादा टाइम ले लिया है, दूसरे को भी बोलना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इंटरवेंशन भी देखिए न। मैं तो चुप हो रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप ज़रा वाइंड अप करें या राऊंड अप करें जो भी करिये मगर बोलना बंद करिये। जो प्वाइंट है आपने रख दिया है। दूसरे लोग भी बोलना वालें हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदया, आज सवाल यह आता है कि कश्मीर पर थोड़ी सी बात कहें तो लोग उछलने लगतें हैं कि इतिहास को मत पढ़ो। जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वह गुलामी की कगार पर चढ़ रहा होता है। इतिहास को भूलना नहीं चाहिए।...(**व्यवधान**)... वे बदलने ही तो आए हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसी लिए तो कान्स्टीट्यूशन रिव्यू हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take this matter seriously. The life of hundreds and thousands of people, the life of millions of people is«ivolved. It is a question of the country. Let us rise above every political consideration and try to make a speech which is of a level. This is applicable to everyone; this is not applicable to Mr. Ahluwalia alone. I request that we should discuss the matter in all seriousness with which the hon. Chairman has allowed it to be discussed. The Home Minister is sitting here. I am sure, he is very keen to get your viewpoint to solve the problem. Let us not talk about history. ये हिस्ट्री बना रहें हैं, वे हिस्ट्री बना रहें हैं Let us go to the bare facts and let us find a solution for it, and I am sure, the Home Minister is keen to get your views.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदया, मैनें यह बात नहीं कही कि इतिहास पढ़ा रहा हूं। मगर किसी भी चीज के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। डाक्टर के पास जाइए...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : नहीं, वे लोग भी इतिहास की बात कर रहें हैं, आप भी कर रहें हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : किसी डाक्टर के पास मरीज जाए तो उसकी हिस्ट्री वह पहले पूछता है उसके बाद इलाज करता है ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : शार्ट में बता दें इतना लम्बा नहीं।

उपसभापति : अच्छा, अब सब लोग खामोशी से उनका भाषण खत्म होने दीजिए। आप डिस्टर्ब करेंगे Then I won't be able to stop him, please जब आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। उनका समस खत्म होने वाला है।उनको खत्म करने दीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदया, कश्मीर के उस पार पाकिस्तान की फिर तैयारी है। खबर है कि ढाई से तीन हजार विदेशी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर तैयार रखा गया है। जैसे ही बर्फ गलनी शुरू होगी, गर्मी पड़ेगी वे भारत की सीमा को क्रास करने की कोशिश करेंगे। उकसे बारे में सरकार क्या करेगी ? सरकार कौन कौन सी कार्यवाही कर रही है ? सबसे बड़ी बात है महोदया कि नौजवान का हाथ जब बेकार होता है, हाथ में जब कुछ नहीं होता है तो लोग उस हाथ में कुछ पकड़वाने की कोशिश करते हैं। कोई बम का गोला पकड़वा देता है कोई ग्रेनेड पकड़वा देता है, कोई एके-47 पकड़वा देता है, कोई कुछ पकड़वाकर देश को कमजोर करने की कोशिश करता है, देश को तोड़ने की कोशिश करता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, please, this is my last request to you. Please sit down. I have to leave the Chair because the Maldivian Delegation is waiting for me. I will come back as soon as the meeting with them is finished . आपका समय से ज्यादा हो गया है ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं क्वेश्चन कर रहा हूं खाली अभी।

उपसभापति : नहीं, मगर क्वेश्चन आप पहले कर लेते ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं क्वेश्चन कर रहा हूं । I am putting questions only.

उपसभापति : दो चार क्वेश्चन्स करके आप बैठ जाइएगा ...(**व्यवधान**)... नहीं बिल्कुल नहीं करना है । मेरे होने तक बिल्कुल कंटीन्यू करना है, मेरे जाने के फौरन बाद बंद करना है और हमारे वाईस चेयरमैन साहब को हैरान मत कीजिएगा ।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्री सुरेश पचौरी**) **पीठासीन हुए**]

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं बता रहा था कि करीब ढाई सौ तीन हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है । वे इंतजार कर रहें हैं बर्फ के पिघलने का और हमारे यहां पर उनकी ऊधम मचाने की शुरूआत होगी । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनसे सख्त, कड़े हाथ से निपेटगी । हर संभव कोशिश की जाएगी कि इनका एक भी आदमी, एक भी ट्रेन्ड आदमी भारत की सीमा पार कर भारत में आकर अपना तांडव नृत्य न कर सके । सबसे बड़ी जो प्राब्लम मैं वहां बता रहा था वह कि हाथ खाली हो तो कुछ न कुछ औजार पकड़वा दो । बेकारी की समस्या बहुत है । कश्मीरी यूथ बेकार बैठा है । वैसे तो 6 महीने बाद जब यह बर्फ पिघलती थी तो अपने कंधे पर शाल और चादरें लादकर सारे हिंदुस्तान के कोने में जाता था और कश्मीरी कपड़ा या कश्मीरी सामान बेचा करता था । पर पिछले 20-30 वर्षों से हमने देखा है कि उन काश्मीरियों पर भी अब बाहर वाले भी कोई ऐतबार नहीं करते । अगर वह सामान बेचने आता है तो उसको डर के मारे घर में घुसने नहीं देते हैं । किसी बाजार में उसको दुकान नहीं लगाने दी जाती । विभिन्न राज्यों में उनको विभिन्न नज़रों से देखा जाता है । यह जो उनका इमेज बन गया है इस इमेज को चेंज करने की जरूरत है । कश्मीरी यूथ को नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने के लिए क्या-क्या पहल सरकार करेगी, कैसे उनको मेनस्ट्रीम में लायेगी ? वहां आम देखा गया है कि कश्मीर के मुख्य मंत्री कश्मीर के मंत्री और मेरे ख्याल से शायद हमारे जो वहां के मेंबर आफॅ पार्लियामेंट हैं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब भी जब कश्मीर जातें हैं तो वह भी कश्मीर पुलिस की सैक्योरिटी नहीं लेते । उन्होनें रिटन हिदायत दी है कि

मुझे कश्मीरी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं दी जाए । ऐसा क्यों हैं ? स्टेट पुलिस की सैक्योरिटी से आपका एतबार अगर उठ गया है, विश्वास उठ गया है तो उसका क्या कारण है ? अगर यह कारण है कि उनसे आपका विशवास उठ गया है तो वहां की जनता कैसे उस पर विशवास करें ? आप उस विश्वास को कैसे बहाल करेंगे ? यह कश्मीर की सरकार,राज्य सरकार का काम है । राज्य सरकार को वहां पर कंफीडेंस रेस्टोर करने की बात करनी है । केन्द्र सरकार क्या उनको कंफीडेंस में लेकर लोगों का जो लॉस्ट कंफीडेस हैं, लोगों का जो लॉस्ट इन्टरेस्ट हैं, क्या उसको रेस्टोर करेगी ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले माना जाता था कि अपने दुश्मनों की रॉकेट की ताकत या बम की ताकत या तोप के गोलों की ताकत का अंदाजा करके बॉर्डर एरिया पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती थी, कोई बड़ा प्रोजैक्ट नहीं लगाया जाता था, क्योंकि दुश्मन उसको खत्म कर सकता था । परन्तु अब तो जब से तीन हजार माइल, चार हजार माइल, पांच हजार माइल की मिसाइल्ज़ आ गई है तब से यह डर सब को है कि दुश्मन का मुल्क हमारे डीप साउथ की भी किसी ऑर्गेनाइजेंशन को, किसी संस्था को, किसी प्रोजैक्ट को आसानी से नष्ट कर सकता है । तो उन चीजों को भूल कर इंबैलेंसेंज़ जो हुए हैं, डवेलपमेंट इंबैलेंसेज जो हुए हैं, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): प्लीज़, कन्क्लूड ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : कश्मीर के इलाके में जो डवेलपमेंट इंबैलेंसेज़ हैं उसको हम कैसे सुधार सकेंगे ? सब से बड़ी बात माइग्रेशन की हुई है । पहले कश्मीर पंडितों का हुआ है । उनको किस तरह से किस स्कीम के तहत हम वापस ला कर उनकी प्रॉपटी वापस दिलायेंगे? मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो वहां के सिख अल्पसंख्यक लोगों ने लिखी है कि 1988, 1989, 1990 में जबरन उनकी जमीनें, जबरन उनके खेत, जबरन उनके बाग, जबरन उनके मकान लिखा लिए गए । क्या यह सब हम उन्हें वापस दिला सकते हैं, क्या इस पर कोई कार्यवाही हो सकती है। ? महोदय, जब तक हम वहां की जनता, जो भारत का अंग है और वे भारत के नागरिक हैं, उनके मन का आत्मविश्वास नहीं जगायेंगें तब तक शायद हम कश्मीर को एक सशक्त राज्य के रूप में उभार नहीं सकेंगें । पैरा मिलिट्री फार्सेस ने, आर्मी ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर वहां पर कदम उठाए हैं और वे भी हम लोगों की तरह ही आदमी हैं । वहां की टोपोग्रॉफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि कब किस तरफ से अटैक हो जाएगा यह किसी को मालूम नहीं होता । मैं उन फिगर्ज़ को कोट नहीं करना चाहता कि कितने आंतकवादी मारे गए और कितने हमारे सैनिक मारे गए या कितना असला पकड़ा गया है,पर एक बात निश्चित है कि यह पाकिस्तान का चक्रांत हैं, पाकिस्तान

का षड़यंत्र है, पूरे सदन को और सरकार को इसमें एकजुट हो कर इस षडयंत्र को एक्सपोज करके खत्म करने की जरूरत है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अहलुवालिया जी, कन्क्लूड करिए। आपके 45 मिनट हो गए हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ...(**व्यवधान**)...

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एश्योरेंस चाहूंगा कि इस मसले के लिए टाइम-फ्रेम कितना है ? कश्मीर का मसला जो खासकर वहां के नौजवानों से जुड़ा है, वहां के अल्पसंख्यकों से जुड़ा है, उस के हल के लिए क्या टाइम-फ्रेम हैं ? वहां के लोगों का ट्रस्ट रिस्टोर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? धन्यवाद।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा(बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कश्मीर जो कभी फूल की जमीं थी, उस की घाटी, फूल की घाटी थी, आज वह शूलों की घाटी और शूलों की जमीं बन गयी है। कश्मीर की समस्या से आज सारा देश चिंतित है और कोई भी सरकार वहां की समस्या को हल करने के लिए, वहां की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाएगी,उस का सारा देश स्वागत करेगा, सारा देश उस के साथ रहेगा। इस बात से देशभर में किसी को कोई संदेह नहीं है। महोदय , अभी जो सरकार है, उस से भले ही हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन यह सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम समझते हैं कि हम और सारा देश उस के साथ रहेगा। अब देखना यह है कि यह सरकार सही कदम उठा पाती है या नहीं।

महोदय, मैं अहलुवालिया जी की तरह इतिहास में बहुत दूर तक नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले एसेंब्ली के चुनाव ने एक माहौल पैदा किया था, वहां के लोगों में विश्वास पैदा किया था। चुनाव को ऐलान होते ही,पुरे देश की बात छोड़ दीजिए, कश्मीरी जनता सरकार के उस डिसीज़न के साथ हो गयी थी और यह बात भी सरकार मानेगी कि चुनाव के बाद की स्थिति ने वहां आतंकवादियों को पीछे ढकेल दिया था।

अगर मंत्री जी ऐसा नहीं मानते तो कहें कि नहीं ढकेला था, लेकिन इतिहास गवाह है कि आतंकवादियों को पीछे ढकेलो गया था और उस स्थिति में बहुत कुछ किया जा सकता था जिस के चलते आज हम कुछ और समस्या की यहां बात कर रहे होते । लेकिन फिर स्थिति ज्यों-की-त्यों बन गयी । ऐसा क्यों हुआ ? इस का जवाब इस सरकार के पास क्या है ? नेशनल कांफरेंस ने इस एसेंब्ली के चुनाव ऑटोनोमी के सवाल पर लड़ा था, लेकिन क्या इतने दिनों में ऑटोनोमी मिल गयी ? क्या जनता की उस आकांक्षा को पूरा किया गया ? नहीं । उस के लिए कमेटी बनी और उस के जो पहले चैयरमेन बने, वह उस कमेटी से अलग हो गए । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी । महोदय, जब हम उस कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करेंगे तो पाएंगे कि यह सरकार भी उस से सहमत नहीं होगी जिस में पहले चैयरमेन के जाने के बाद से एक ही आदमी के सारे लोग भर लिए गए थे जिस की चर्चा उस समय भी हुई थी । महोदय, उस कमेटी ने जैसा काम किया, मैं चाहंगा कि माननीय मंत्री जी अपना जवाब देते समय उस पर भी कमेंट्स दें । हालांकि चुनाव के बाद स्थिति में सुधार आया था, लेकिन उस के बाद आज इस बात की चर्चा है कि यह करप्सन रेम्पेंट हैं और विकास कार्यों की स्थिति दयनीय है । क्या वहां जो वित्तीय अनियमितता है, करप्शन है और विकास कार्य जिस तरह से ठप्प होने की कगार पर हैं,उस स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से क्या पहल हुई हैं या इस मामले पर आप इसलिए चुप हैं कि जिस पार्टी की वहां सरकार है, उस का समर्थन लेकर आप यहां अपनी सरकार को कायम रखना चाहतें हैं । इस मामले पर भी स्पष्टीकरण आना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूर्व-वक्ता की सारी बातों का समर्थन करता हूं और मेरा मत है कि वहां की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार वहां के लोगों को अपने कांफिडेंस में ले । पाकिस्तानी घुसपैठियों से कश्मीर आतंकवादियों को अलग कर के उन्हें विश्वास में ले और इस के लिए जरूरी है कि वहां की जनता की आकाक्षांओं को पूरा किया जाए क्योंकि यह किए बिना कुछ नहीं हो सकता । महोदय, दूसरा मुद्दा मैं लेना चाहता हूं कि हाई जैकिंग के बाद और कुछ आतंकवादियों को जेल से छोडने के बाद जब यहां चर्चा हुई थी , मैने पूछा था एक प्रश्न के संदर्भ में तो गृह मंत्री जी ही थे जिन्होनें उस वक्त जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था । मैनें पूछा था कि हमारी आंतरिक कमजोरियां क्या हैं ? उन्होनें सिर्फ इतना कहा था कि सबको मालूम हैं । उन आंतरिक कमियों की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा और कुछ सजेशन्स देना चाहूंगा । 1997 में जब तत्कालीन प्रधान मैं इशारा करना चाहूंगा और कुछ आतंकवादियों से बातचीत करने की, चर्चा करने की पहल की थी तो उस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था और कहा था कि इस बातचीत की पहल से हमारी सेना का मनोबल गिरा है, वहां की सरकार का मनोबल गिरा है और वहां की जनता का मनोबल

गिरा है, लेकिन हाई जैकिंग के बाद जब हमने आंतकवादियों को जेल से रिहा करके उनको उनके असली मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वे पाकिस्तान जा सकते थे, कहीं और जा सकते थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे सेना का मनोबल टूटा या नहीं, वहां की सरकार का मनोबल टूटा या नहीं और जनता का मनोबल टूटा या नहीं ? हम यह स्वीकार करेंगे कि वह स्थिति ही ऐसी थी कि आपको करना पड़ा, लेकिन उससे मनोबल टूटा या नहीं, उससे हमारे अर्द्ध सैनिक बलों का मनोबल टूटा या नहीं, जनता का और सरकार का मनोबल टूटा या नहीं ? उनका मनोबल तोड़ने के लिए आपकी कई कारगुज़ारियां काफी है और इसलिए वहां स्थिति बिगड़ती गई ।

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि आप अविलम्ब उस समस्या के निदान का उपाय करें । मैनें अभी सेना का मनोबल गिरने की बात कही । हमारे सी.आर.पी.एफ. के 30,000 परसोनल कश्मीर में हैं और उनकी वहां भूमिका है और कारगिल को लेकर जो समिति बनी थी उसने अपना कमेंट दिया एक पैरा में कि आतंकवदियों के, घुसपैठियों के हथियार इतनी उन्नत किस्म के हैं कि हमारें अर्द्ध सैनिक बलों के पास वे हथियार नहीं है जिससे कि वहां सेना को जाना पड़ा और कमेंट हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि सेना की भूमिका अर्द्ध सैनिक बल की हो गई और अर्द्ध सैनिक बल इतने निहत्थे थे कि उनकी स्थिति, उनकी भूमिका साधारण पुलिस की हो गई । मैं जानना चाहता हूं कि उनको इस स्थिति से उबारने के लिए आपने क्या किया है ? इससे भी गंभीर बात यह है कि जिसकी तरफ हम आपको इशारा करना चाहेंगे कि जो हमारे अर्द्ध सैनिक बल वहां पर आतंकवादियों से जूझ रहें हैं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में अभी तक आपकी कोई नीति समझ में नहीं आती है । शिकायतें मिलती हैं कि हार्ड एरिया में हैं यानी जो आंतकवादियों से जूझ रहें हैं, उस एरिया में हैं, वहां से फिर उनको नार्थ-ईस्ट रीज़न में उसी काम के लिए भेज दिया जाता है । होना यह चाहिए कि जो कुछ काल तक आंतकवादियो से कश्मीर में जूझने के लिए वहां से उनको जाना है तो कुछ दिन वे पीस एरिया में रह लें और फिर उनको वहां से दूसरी जगह भेजा जाए । ऐसा न करके उनको हार्ड एरिया से हार्ड एरिया में भेजा जा रहा है और सबसे गंभीर बात तो यह है कि जो पीस एरिया में हैं वे निरंतर पीस एरिया में ही है । दिल्ली में जो इस बल के सबसे बड़े अधिकारी हैं,ए.डी.आई.जी. रैंक के जो अधिकारी है, वे 15 साल से दिल्ली में जमें हुए हैं और 3 साल के लिए भी कश्मीर में नहीं गए । मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता, पोस्ट ही काफी है । ऐसे कितने ही आफिसर हैं दिल्ली में जो दिल्ली से बाहर कुछ समय के लिए जाते हैं और फिर दिल्ली में आ जातें हैं- दिल्ली से पीस एरिया से पीस एरिया में और फिर वहां से दिल्ली आ जातें हैं और इस तरह से 11 ए.डी.आई.जी. रैंक के 11-12 कमांडेंट रैंक के ऐसे अधिकारी दिल्ली में हैं जो दिल्ली से कुछ

अदल-बदल और अदल-बदल से फिर दिल्ली में रह रहें हैं और उनकी कारगुज़ारियां ऐसी हैं कि वे जो ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रहें हैं, शिकायतें आ रही हैं. कि वे कम्युनल आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रहें हैं, जबकि हमारी एन्युअल रिपोर्ट में हैं कि सी.आर.पी.एफ. एकदम धम्रनिरेपक्ष आधार पर चलने वाला अर्द्ध सैनिक बल है । देश के विभिन्न कौनों से, विभिन्न जातियों को उसमें रिप्रेजेंटेशन है और उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग कम्युनल आधार पर होगी तो उनकी ऐफिशिएंसी कहां तक रहेगी, नहीं रहेगी । आपको मालूम है कि एक बडे अधिकारी की चेयरमैनशिप में अफसरों का एक ऐसोसिएशन खड़ा हो गया, उस जगह से खड़ा हुआ, जहां सी.आर.पी.एफ . का जन्म हुआ था.... गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से उसे भंग करना पडा । हम यहां आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहें हैं लेकिन सुरक्षा को सुरक्षित करने वाली जो हमारी सी.आर.पी.एफ. जैसी महत्वपूर्ण आतंरिक एजेंसी है, उसके अंदर अधिकारियों के चलते इस तरह के अंसतोष हों, यह ठीक नहीं है । इससे उनकी ऐफिशियेंसी खत्म होती है । मैं समझता हूं कि कश्मीर में अर्ध सैनिक बलों की ऐफिशियेंसी बढ़नी चाहिए और उन्हें उम्दा हथियार देने के साथ-साथ उनकी जो समस्याएं हैं, उनका निदान किया जाना चाहिए । महोदय, ट्रांसफर पोस्टिंग की एक निश्चित पालिसी गृह मंत्रालय तैयार करें और उसको अपने हाथ में ले । महोदय, यह सही है कि किसी एक के ऊपर इलज़ाम नहीं मढ़ा जा सकता और हम यह उम्मीद भी नहीं करते कि छूमंतर में कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी लेकिन जो हमारी आंतरिक कमजोरियां है, जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, उन पर हमें नियंत्रण करना ही चाहिए । हम उन पर निंयत्रण पा सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं हैं बशर्ते कि उस समस्या का सही ढंग से ऐसेस्मेंट किया जाए और जो तरीका अपनाने के लिए कहा जाए, वह अपनाया जाए और जो उपाय बताएं जांए, उन पर अमल किया जाए ।

महोदय, हमारे प्रथम वक्ता श्री गुलाम नबी आजाद जी ने सुझाव दिया कि कश्मीर के उसे इलाके के जो सांसद हैं, चाहे वे कहीं से भी चुन लिए गए हैं, उनकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि अहलुवालिया जी का कमेंट सही नहीं था जब उन्होनें कहा कि वे कहां से चुने गए हैं ? मुझे समझ नहीं आया कि वे क्या कहना चाहते थे । यह तो हम पर लानत हैं कि हमने ऐसी स्थिति वहां बनने दी और उसको सुझाव दिया कि जो सांसद वहां की समस्या को जानतें हैं, उससे जो रूबरू हो रहें हैं, जूझ रहें हैं, जिनके भाई और बंधु वहां मारे गए हैं, जिनकी आंखों में आंसू है और आज तक समस्या का निदान न होने से जिनकी आंखों से आंसू बह रहें हैं, जिनकी छाती छलनी है ऐसे सांसदों और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर गृह मंत्रालय और इस सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम इन

लोगों को कान्फिडेंस में लें।

महोदय, अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह हमें वहां के लोगों को कान्फिडेंस में लेना चाहिए और वहां की जो भी समस्या है, उसका निदान निकल सके, ऐसे उपाय करने चाहिए और इस संबंध में मानीनय गृह मंत्री जी को एक घोषणा करनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लुंगा, मैं अपने दूसरे साथियों के विचारों को भी सुनना चाहूंगा। इसलिए अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam):Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. The problem in Kashmir is a long-standing problem, and at various points of time, a number of packages have been announced. I do hope, there will be a political solution to this long-standing problem. Sir, on the question of autonomy, a special status for the Kashmiri population has been one of the major propaganda of the various outfits. Now, this issue has not been properly addressed. Sir, there is an impression in the entire country that a special constitutional provision for Kashmir was enough to save this part of our country. But, in a real sense, as the initiator of this Motion, Ghulam Nabi Azadji, said, the major root cause of this is the unemployment problem. The militant outfits recruit a number of young boys and girls. They are being apprehended and, while searching for them, quite a number of innocent people, innocent families, are subjected to harassment. In such a situation, the problem is further aggravated, and our approach towards a military solution could not found to be effective in any part of the region. It was not effective in any part of the North-Eastern Region, leave alone Kashmir. We always tried to bring in Pakistan. Whenever such a situation arises, we say that Pakistan is helping the militants, the ISI's hand is there and, most of the time, we also try to shift the responsibility on to the State Government. Even the present State Government, which is an ally of the Union Government here, is feeling that, since the Government is there, it is their problem. But, in totality, was there any national approach to deal with the problems of the Kashmiris? There needs to be a pragmatic and a concrete action plan which can really heal the wounds of the affected Kashmiri people. The question of communal forces comes afterwards. The first and the foremost route-cause is unemployment among lakhs and lakhs of unemployed youth. When they have no opportunity for appointment in the Government or in any public sector undertaking or in any other private establishment, and even when there is no

room in the tourism sector, which has greatly suffered during the last ten years, the misery of the common people is beyond imagination. The North-Eastern Region was given some hope with various packages. There was also a mention by some of the hon. Members about Jammu and Kashmir, not only today, but even on earlier occasions; they should have been given more economic packages, like the packages that are being given to the North-Eastern Region by the Government. It is absent, We have seen that there is some deficiency in the efforts of the Government. I hope the Union Government will be formulating a specific package for the Kashmiri people so that they do not get recruited by the militant outfits or their emotion cannot be exploited by the militant outfits. Further, a healing approach has to be undertaken by the Indian Government. Harbouring terrorists by the natives is a problem which the North-Eastern Region is also facing. When the army — I have a personal experience — and the paramilitary forces are deployed, they always try to stay back in the urban areas or in good areas where they have good communication and other facilities and good vehicles to travel. Even the armed forces are not able to trace the actual hideouts of the terrorists — leave alone the paramilitary forces - and apprehend them. They try to reach the actual focal points. In that case, after the terrorists leave that particular place, the common man is harassed. It has further aggravated the problem; it has created a disillusion among the youth. Sir, it is very fortunate that the hon. Home Minister has declared that the Government is willing to start the process of negotiations with the militant outfits. But there is also a resentment that why only the militant outfits; why other sections of the Kashmiri people are not taken into confidence, to have a permanent solution. So far as the point of autonomy is concerned, it is a primary issue. It should not be ignored. There should be a special national debate on this issue. For the healing touch, there should be a number of exchange programmes from various States - cultural exchange, economic exchange, training programmes, exchange of students; excursion activities, or similar other facilities should be given to students to come out of the Valley of Kashmir to see the other parts of the country so that they can mix and they can feel at home. Till today, the people of Kashmir and the North-East region have been having a feeling of isolation.

Then, Sir, I hope the Government will take a serious note, so far as the issue of surrender is concerned. The surrender by militants has another dimension. A large number of militants had surrendered in the

North-Eastern region. Many of them were assured of employment at the Government leveL They were also assured of bank loans for self-employment. But it is very unfortunate that there is no specific package for them, except granting of some loans to the surrendered militants. Many of the surrendered militants were utilized by the military and paramilitary forces to apprehend the militant groups.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude, now.

DR. ARUN KUMAR SARMA: They were not only utilized as an instrument, but, in fact, they were not given proper healing touch, proper help to come to the mainstream, to be a part of the mainstream. For example, the Annual Report of the Ministry of Home Affairs says, "From 1990 onwards, 3683 militants have surrendered till August 24, 1999. These militants had also surrendered a large quantity of arms and ammunitions. The Government of India has approved raising two battalions for the Central Paramilitary Forces which will mainly comprise of these surrendered militants. So far 921 surrenderees have been recruited in these battalions. These surrendered militants will also be covered under the Prime Minister's Rozgar Yojna, or State's self-employment schemes for establishing a permanent source of income. Sir, the Prime Minister's Self-Rozgar Yojna is not serving any purpose. Similar is the experience in the North-Eastern region also. I think, there should be a specific recruitment drive for those surrendered militants so that we can give a proper assurance, a proper guarantee, to those who have already surrendered. With these words, I conclude, Sir. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अब हमारे पास कुछ अतिरिक्त नाम है जिनके नाम नोटिस में नहीं थे । मैं उन सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षेप में वे अपनी बात कहें । श्री जेनश्वर मिश्र ..... अनुपस्थित । श्री मार्गबन्धु ।

SHRI R. MARGABANDU: Sir, keeping in view that the security and the integrity of the Indian nation should be in-tact and keeping the diplomacy at the highest pedestal, on behalf of the AIADMK party, I request the Central Government to take appropriate action to solve this problem. My suggestion would be that an all party meeting can be convened to discuss this problem and to chalk out the ways and means for the solution of this problem. Now, Sir, I am given to understand that

geographically, the area of Kashmir is 19,000 kilometres; and the area of Ladakh and Jammu is 95,000 and 25,000 kilometres respectively. I am given to understand that the people of both Ladakh and Jammu do not want autonomy. Sir, the people in Kashmir alone are talking about autonomy. They are talking about greater autonomy. I am given to understand that it is not that all the people there are talking about autonomy, it is only a fraction of the people who are asking for this autonomy and independence. The people of Ladakh and Jammu look towards India for patronage. There is also a feeling that there is a small package for these two regions and there is a greater package for the Kashmir valley. Sir, for these people the problem seems to have started in the year 1986-87 when there was a rigging of the elections in 3-4 constituencies. Since then Pakistan is trying to encourage the discontented people, and it is only from there all the problems started. Having failed in 1947 and 1965 wars, Pakistan now somehow wants to annex a portion of Kashmir. When Pakistan is not able to achieve Kashmir by open wars, it is trying to achieve it by proxy-war. Sir, I am given to understand that three organisations, namely Hizbul Mujahideen, Harkatul Ansar and Huriyat Council Group are fighting for the independence of Kashmir and for that the ISI and other separatist movements are supporting them. Some Afriacan countries, Saudi Arabia and some Islamic countries are also supporting these terrorist activities of Pakistan. They give pinpricks; Sir, their aim is not that they want something out of it. They only want to create trouble in India. They do not want peace to prevail in that area. They want that there should always be threat and fear. They want to create instability in that part of India, thereby achieving their objective. But, ultimately, Sir, we must see, that this continuing problem on this border area should, at any rate, be solved.

I am also given to understand that the people of Kashmir feel that thek life is insecure. There are attacks on them from the terrorists. From the security point of view, searches are made by our security forces, and the people feel completely dissatisfied. They feel that their life and property are not safe. That is why this sense of insecurity has cropped up in their mind. I request that the Central Government should solve the problem. It should see that no fraction of the people is carried away by the Pakistani terrorists' activities. The people should be safe. For all these things, the Government should take all effective steps.

I am also given to understand that the people of Ladakh do not want to align with the Kashmir area because, they feel, that the people from the Kashmir area want to dominate over their area. They do not want to align with Pakistan either. They want to be with India always. Their lives and their interests have to be safeguarded. I request that a political solution to that effect should be arrived at, by the Central Government.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. Most of the Members have successfully projected the situation that has been prevailing in Jammu and Kashmir. It is quite alarming. Not a day passes, without a violent incident.

Sir, I should not blame any particular Government. But the problem has to be solved, and normalcy has to be restored. The people are virtually sandwiched between the security forces and the militants in that area. I should say that they have been driven between the deep sea and the devil. That is the situation prevailing in Jammu and Kashmir. This place, which has been described as the Jewel of India, is virtually in flames now. The Government has to seize the matter and initiate efforts on a war-footing.

The recent massacre of the Sikhs speaks volumes of the problem. There are some naked, ground realities which have to be taken notice of, by the Government.

Sir, underdevelopment is one of the root causes for all these problems. The people are living in utterly miserable conditions. Their pecuniary circumstances are forcing them to indulge in violence. Nobody prefers to live a violent life, indulging in immoral or illegal activities. Virtually, they have been driven to this. I do not Want to say vvho is responsible for this. But that is the situation. Virtually, a war-like situation is prevailing there.

I should say that the successive Governments in Jammu and Kashmir have not initiated any efforts to take the people into confidence, and the credibility of the Governments have been at a very low ebb.

Sir, the people are unwilling to participate in the electoral processes. The persons are being elected with just 5, 10 or 15 per cent polling. So, this is the situation. Democratic institutions have already been destroyed. Civic life is in total disarray. I will make some suggestions, Sir.

The Government should have a multi-pronged attack, strategy. The Home Minister's claim that the pro-active role of the Government has contained the violence is not true. It is not true at all. Sir, what is the number of militants who have been captured, who have been convicted? And the witnesses are unable to come and depose before the courts because the Government is not in a position to protect their lives. You cannot blame them. The legal system has got its own loopholes and lacunae. So, that system has to be strengthened. And laws should be made more stringent so that it acts as a deterrent for the persons who are indulging in violence. Sir, my suggestion is that a special package should be evolved for the development of the area and the development should be in an integrated manner so that the living conditions of the people are improved, so that the youth are not lured or attracted by the militant outfits which are recruiting these people and forcing them to indulge in violence. Motivation of the people is very important. The people of Kashmir seem to be totally demoralized. They have got no confidence in elected Governments because elected Governments have not lived up to their expectations. With all the reasons that people are aware of, the world is aware of, we may extend any reason which may happen to be justifiable, but, ultimately, as the earlier speaker Mr. Azad was telling us, earlier, 70 per cent were local militants and 30 per cent were foreign elements. At least, the United Front Government and the BJP Government brought down that from 70 per cent to 30 per cent. According to the figures, now, 30 per cent are local militants' and 70 per cent are foreign militants. Sir, Mr. Azad was there as a Minister of the Government which ruled for- 3 1/2 to 4 decades and was virtually in a power-making position. He should have initiated some measures. He or his Government should have addressed the matter. I am not personally blaming a particular Government. Now, the entire country has to pay the penalty.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I do not want to take much time, Sir. I am a disciplined Member. The earlier speaker....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please do not compare with earlier speakers. Their names were there in the List of Business.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I have got a right to compare. The earlier speakers wee given 45-50 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): If you read the "Practice and Procedure of Parliament" by Kaul and Shakdher, it is very clear at page 440. Members whose names are not there in the List of Business, cannot raise questions.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Is it being practised in a good spirit?

SHRI NILOTPAL BASU (West bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I agree with him. Any rule should be applied in an even-handed manner. The other day, we had a discussion here. We were strictly following the time-limit. Within one and a half hours, the Calling Attention was over. We were being repeatedly told about the rules, by the Chair. If you set different standards and if people question, I think it is not unfair. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI):We cannot overrule the hon. Chairman.

SHRI NILOTPAL BASU: Please apply the rules uniformly. I am sorry. For some motions, some discussions, you set some parameters and for today's discussion, you set different parameters. That is not acceptable. If you go by the rules, then, the person who is initiating the debate is supposed to speak for seven minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI):We cannot overrule the hon. Chairman. It was the hon. Chairman who was in the Chair at that time.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: It is the duty of the Chair also to protect the interests of the Members here, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Okay. Please continue.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I do not want to go into any controversy. Yesterday, what happened? When the Gujarat question had come up, I wanted to pose a question about Andhra Pradesh i was told, "No, only questions about Gujarat should be raised." And when the issues relating to the other States have come before the House, the discussion was extended up to Pakistan and Malaysia. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please come to the point.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: We, being the new Members, expect justice. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I would like to make one submission in this regard. We are noticing it for a long time that different persons sitting in the Chair are giving different rulings. So, there is a lack of uniformity in the rules. May be, all the Members in the Panel should see the Chairman and bring out some uniform rules which are applied in all situations.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI: You can give such suggestions in the meeting of the Rules Committee.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I do not want to enter into any controversy. We, the new Members, expect some encouragement. We are not able to put even the supplementaries. All the senior Members are getting a chance to speak on various topcis and the new Members are not allowed to put even supplementaries. This is the opinion of the majority of the Members. I am sorry to say that I am trasgressing my limit. Before I conclude, I call upon the Government to take all measures to restore normalcy, create confidence among the people and bring them to the mainstream of life by initiating various steps. Thank you.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala):Mr. Vice-Chairman, Sir, many important points have been raised by my colleagues here. I do not want to repeat those points. The hon. Home Minister has explained here that the Government is pursuing a three-pronged strategy. One is, pro-activery tackling with the help of the security forces the cross-border terrorism. The second strategy is, accelerating economic development and also redressing the genuine grievances of the people. The third strategy is, initiating a dialogue within the constitutional framework with the alienated sections of the society, specially, the misguided youths. This third strategy has not been properly explained in the statement. He has dismissed the third strategy in one single sentence, that is, the last sentence of the statement. "The Government remains committed to initiating a dialogue with the alienated sections of the society, specially, the misguided youths within the constitutional framework." I wish to confine my questions to this particularly important area. Now, in the recent weeks, we see a spurt in the activities of the terrorists and there were a lot of statements from the side of the organisations who were banned. Many of them were put behind bars.

In the recent weeks, the Government has released certain leaders of the All-Party Hurriyat Conference. The All- Party Hurriyat Conference has been making a lot of statements. Even in today's newspaper, *The Hindu,* the deader of the All-Party Hurriyat Conference, Shri Syed Ali Shah Geelani, has said something. I quote: "The Hurriyat would have no objection even if a plebiscite was conducted in the three regions of the State, that is, Jammu, Kashmir and Ladakh and the Pakistan-occupied Kashmir, to ascertain the wishes of the people. The Hurriyat is ready for any solution that is acceptable to India, Pakistan and the people of Kashmir. " He further said: "Even the Dixon plan of dividing Kashmir on religious line was acceptable to them." It is not that only the Hurriat leaders are making statements. I saw many statements of Syed Mir Quasim, former Chief Minister of Jammu & Kashmir. There is another group called the Kashmir Study Group. They are also making proposals. They are also making statements for dividing Jammu & Kashmir into three regions--the Kashmir Valley, the Jammu area and the Ladakh area. They are also proposing a plebiscite. They are also proposing separation of Kashmir from these two regions. There are statements from JKLF also. Yaseen Malik's statement is also there in "The Hindu" and "The Asian Age" today. So, a lot of statements are there, Sir. These organisations are now very active. There are some Press reports also. Today, in "The Asian Age", the heading is "Excitement in Valley over unseen U.S. hand". Actually, a spurt of these activities happened after the visit of Mr. Clinton to India and the discussions with Mr. Clinton. Sir, we have been taking a consistent stand that this is a bilateral issue;.this should be settled through bilateral discussions between India and Pakistan and we should not allow any third party to intervene, because we know the interests of certain third parties, the imperialist countries, particularly the United States of America. If they get hold of Kashmir, not only can they control India and Pakistan but they can also control the entire area. So, they have an interest there; that is why, for all these years, since 1953, they are against India's stand. They are creating problems. Now the spurt of all these activities is taking place immediately after Mr. Clinton's visit and certain discussions. I would like to know from the hon. Minister whether <ie present spurt of activities and discussions has anything to do with Mr. Clinton's visit or not, or whether the Government has changed its consistent position, not to allow any third party to intervene in this matter. This is a matter concerning the unity and integrity of India. This is one

aspect that I would like to know from the hon. Home Minister.

My second question is this. Now, there are talks about dividing Jammu & Kashmir into three regions-the Kashmir region, the Jammu region and the Ladakh region, and also giving similar autonomy to these three regions. A section of National Conference leaders are toying with this idea. Farooq Abdullah also, here and there, mentioned this idea, and all these new organisations-the All Parties Hurriat Conference, the JKLF, the Kashmir Study Group—are making similar statements, Sir. I think, this is a very, very dangerous proposition. If we allow similar regional autonomy to Kashmir, Jammu and Ladakh, then Kashmir is gone. We know the present reality, Sir, that there is a concerted effort by Pakistan-sponsored terrorists to drive away the Hindus and the Sikhs from Kashmir to other regions. Sir, we know the passion of the people. If similar happenings are taking place in other parts of Kashmir, in Jammu and Ladakh, what would be the result? Kashmir is gone. So, we should not encourage this sort of an idea of giving similar regional autonomy to these three regions. I would like to know from the hon. Home Minister what the perception of the Central Government is on this crucial question. This will be a trap and we should not entertain this idea. We should make our position clear and we should also try to educate the people about the dangers inherent in it.

There is only one more question. Earlier the Government has stated that it would come up with a white paper on the activities of the ISI. The Government has not come up with that white paper. My friend has raised a question of calling a meeting of all political parties or MPs from Jammu and Kashmir. If something cannot be said openly, of course, it is always better to have a closed-door meeting on the acitivities that are going on, the dangers and the steps that we should take. I would like to request the hon. Home Minister to take the initiative of calling all political parties for a closed-door meeting on the present situation because there is an ominous feeling. Though in certain areas certain actions are taken, overall the situation is slowly drifting. I would like to have clarifications from the hon. Home Minister on these three major points. Thank you.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY(West Bengal):Mr. Vice-Chairman, Sir, the Calling Attention Motion, this afternoon, refers to the issue of internal.security problem with reference to the State of Jammu and Kashmir and, indeed, the first question is whether the time has come or

not to differentiate between the concept of what we call internal security and what is actually going on in Jammu and Kashmir, which is a proxy war. The internal security pertains to, essentially, an internal threat. A proxy war, by all definitions, is an external threat. I think we should now differentiate between the two and organise ourselves accordingly. As far as the conflict in Jammu and Kashmir is concerned, the House knows and we all know that this is a low intensity conflict, a war with Pakistan, an undeclared proxy war by Pakistan, as a revenge for Bangladesh. Pakistan will not stop its offensive in Kashmir until it realises its aim of liberation of Kashmir this time through a low intensity conflict. The conflict in Kashmir actually comprises two major conflicts. There is one conflict along the line of control which involves direct confrontation between the regular Armed Forces of the Indian Union and Pakistan. There is a separate but interlinked conflict in the hinterlands of Kashmir, which is an insurgency, a proxy war. It is being supported, aided and abetted by Pakistan. The hon. Home Minister has made a statement where he has specified several issues on which the Government is acting, as is mentioned, on a three-pronged approach. But I think, the basic question being addressed, the basic concern being expressed, by all the Members of this House is one. How is the Kashmir problem to be solved? Mr. Vice-Chairman, Sir, on 22nd February , 1994, both Houses of Parliament passed a Resolution unanimously, which, among others, had demanded that Pakistan must vacate the areas of the Indian State of Jammu & Kashmir which they had occupied through aggression. This pre-supposes that the people of, what we call, Pakistan occupied Kashmir, on the other side of the Line of Control, are willing and desirous to reunite with the rest of Kashmir, within the Indian Union. This is a matter which we should consider dispassionately. If it is our dispassionate consideration that the people on the other side of the Line of Control, in the Pakistan occupied Kashmir, do desire to join the Indian Union, then only this Resolution which was passed by both Houses of Parliament must be considered sacrosanct. If we feel that this does not correspond to the actual realities on the ground, is it time to consider another alternative to which some Members have hinted at, but not spoken openly? What is India's position on Kashmir? India's position on Kashmir is, as I just explained, the areas, which we call Pakistan occupied Kashmir, are part of the Indian Union and must be given back to Kashmir. We must dispassionately consider this issue, keeping in mind the

attitude, the environment, on the other side of the Line of Control, as well as our own capabilities. Whether this is a feasible or a practicable proposition? What is Pakistan's view on Kashmir? Pakaistan's view on Kashmir is, as per the United Nations Resolution of 1948-49, a plebiscite must be held in the areas of Kashmir which the United Nations claims is a disputed area. Our position is also very clear on this subject. The circumstances, under which this Resolution was passed, have totally changed and the ground conditions under which such a UN Resolution was to be implemented no longer exist. Hence, the conditions, the approaches of India and Pakistan are diametrically opposite. On the face of it, seems incapable of resolution. We have decided and determined , and quite rightly so, that the resolution of Kashmir issue is a bilateral matter. It should be resolved between India and Pakistan. The attitudes, the approaches adopted by both the countries are directly conflicting with each other. Is there now a time when all sections of this country, as represented in this august House, seriously examine a third proposition, notwithstanding the Resolution that was passed in this very House? Is the solution of the Kashmir problem a division of Kashmir, based on the Line of Control? Because we are quite clear that we are not going to give to Pakistan what we hold in Kashmir. Not even an inch of it. Equally, it is for us to assess the practicability of attempting to recover the rest of Pakistan because this certainly will not be a voluntary rejoining with the country. Now it is for the representatives of all sections of the people of this great country to decide what should be the way forward to resolve the Kashmir issue. The answer will not be easy. The answer will not be quick. The answer will most probably be rejected by many sections of the people, to begin with. Nevertheless, my submission to the Government is: Should we practicably begin a quest on these lines?

श्रीमती कुमकुम राय (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का और कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजन प्रसाद यादव जी का जिन्होनें मुझे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यहां जम्मू और कश्मीर पर चर्चा हो रही है । इसी कश्मीर के विषय में बहुत पहले किसी शायर ने कहा था कि –

"अगर जन्नत कहीं होती जमीं पर,
यहीं होती, होती यहीं पर"

महोदय, धरती की यह जन्नत यहां के बार्शिदे आज ज़हन्नुम की आग में झुलस रहे हैं। उनकी तपिश से यह मुल्क अछूता नहीं हैं। मैं अपने पूर्व वक्ता आदरणीय श्री गुलाम नबी आज़ाद के विचारों से सहमत हूं और उन बातों को दोहराकर सदन का समय ज़ाया नहीं करना चाहती हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि जम्मू और कश्मीर पूरे देश की दुखती राग है और मैं भी इससे अलग नहीं हूं।

महोदय, डा.फारूख अब्दुल्ला जी की सरकार बनी 9 अक्टूबर, 1996 को और उनके द्वारा स्थिति में सुधार लाने और शांति लौटाने का दावा किया गया था। उस दावे की सच्चाई की जांच के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूं कि 9अक्टूबर, 1996 से अब तक 25 सामूहिक हत्याकांड वहां हो चुके हैं जिनमें 302 मासूमों की मौतें हो चुकी हैं। न जाने कितनी माताओं की कोख उजड़ गई, न जाने कितनी बहनों की मांग सूनी हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ और लावारिस हो गए और ऐसे हालात में जब भी जम्मू और कश्मीर के बारे में बात होती है, चर्चा होती है तो हमारे तमाम राजनीतिक दलों के दिमाग में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वहां पर जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार मानवता की हत्या की जा रही है, उससे निपटने के लिए सभी लोगों को एकमत होकर कोई उपाय खोजना चाहिए।

महोदय, हमारे सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में पिछले वर्षों में एक हजार से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया और लगभग 700 पाक समर्थित आंतवादियों को पकड़ा। बावजूद इसके, कारगिल युद्ध के दौरान और उसके बाद घाटी में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है। महोदय, कारगिल की जो घटना हुई, उस प्रकरण में हमारी सरकार की जो कमजोरी रही, सुरक्षा में जो खामियां थी, उसका परिणाम हम आज भुगत रहें हैं। महोदय, हमारे सुरक्षा तंत्र और सूचना तंत्र की कमजोरियां से कारगिल में घुसपैठ हुई, विदेशी बाहर से आए, उन्होनें वहां बंकर बजाए,विदेशी अस्त्र-शस्त्र का जखीरा खड़ा किया और हमारी सरकार कानों में तेल डालकर दिल्ली में चुपचाप सोती रही। इसके परिणामस्वरूप आज तमाम आतंकवादी हमारे यहां घुस आए हैं। अब उसमें एक और इज़ाफा हुआ है आत्मघाती दस्ते का। पहले तो हमने यह श्रीलंका के बारे में में ही सुना था कि वहां ऐसे आत्मघाती दस्ते हैं। अब ये हमारे यहां भी घुस आए हैं और जिस प्रकार से ये लोगों की हत्यांए कर रहें हैं, वह अत्यंत दर्दनाक हैं। महोदय, शरीर के चीथड़े-चीथड़े हो जातें हैं और मरने वाला अभागा व्यक्ति अंतिम संस्कार के काबिल भी नहीं रह जाता। इस प्रकार दिनों-दिन यह हिंसा अनेक रूप धारण कर रही है और इसके ये रूप हम जम्मू-कश्मीर में देखने लगें हैं, भुगतने लगे हैं । इस समय वहां लगभग 3,500 आतंकवादी सक्रिय हैं जिनमें 90 प्रतिशत

विदेशी मूल के हैं । इसके अतिरिक्त लश्कर-ए-तोयबा और अलबदर के आत्मघाती दस्तों का आना जारी है । छत्तीसिंहपुरा में 40 सिखों की जघन्य हत्या ने पूरे विश्व का झंझोड़ करके रख दिया । जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौर पर थे, उस समय पाक समर्थित आंतकवादियों के द्वारा इन सिखों की जघन्य हत्या के पीछे पाकिस्तान का जो ओछा मकसद था- हमें इस बात की खुशी है कि वे अपने इस ओछे मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हमारे गृह मंत्री ने हुर्रियत कान्फ्रेंस के बंदी नेताओं को छोड़ दिया है । कश्मीर के पंडितों ने और उनके संगठन ने जो पुनर कश्मीर के प्रवक्ता युवराज जैना है, इसका विरोध करते हुए कहा है कि गृह मंत्री को उन लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए जिन्होनें वर्षों तक इस देश को बंधक बनाए रखा । इसके अतिरिक्त आज सीमा पार से आतंकवाद एंव छायावाद से पीड़ित 35 लाख कश्मीरी पंडितों की समस्यांए अलग दिखाई दे रही है । जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के नेता यासीन मल्लिक रिहा होने के बाद जब पत्रकारों से मुखातिब होते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहतें हैं कि मैनें ही, या हम लोगों ने ही पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती साहब की बेटी रूबैया का अपहरण किया था और उसके बदले में कट्टर आतंकवादी छुडांए गये थे । इसके अलावा अभी जो कंधार प्रकरण हुआ, उसमें भी हमारी सरकार ने एकदम खूंखार आतंकवादियों को गोद में बिठाकर कंधार ले जाकर उन्हें सौंप देने का जो काम किया है, इन सब घटनाओं से भारत की छवि-ऐसा लगता हे कि हम अक्रामक नहीं , हम डिफेंसिव होते जा रहें हैं, हम दबते जा रहें हैं, हम अपने ही आंगन में सिमटते जा रहें हैं और और हम अपने की बचाव में लगे हुए हैं । हमें ऐसी नीति का परित्याग करना होगा । हम जरूर शंति के पुजारी है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ही आंगन में आकर हमारे ही नागरिकों के हितों से खिलवाड़ किया जाए,हमारे ही जीवन से खिलवाड़ किया जाए । हमारी सरकार ने किस प्रकार कारगिल के युद्ध के दौरान भी तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को सुरक्षित रास्ता दिया था । यह सब बातें हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारे यहां कौन सी नीति है जिसमें हम अपने घर के आंगन में भी सुरक्षित नहीं है, हमारी माताओं-बहनों की इज्जत और आबरू असुरक्षित है हमारे बच्चों का भविष्य असुरक्षित है और सीमाओं पर भी हमारे सैनिकों का मनोबल घट रहा है, आज जो घुसपैठिए आतंकवादी हमारे देश में आ रहें हैं, जो भाडे के सैनिक आ रहें हैं पाकिस्तान के भेजे हुए लोग आ रहें है, उनके पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हैं, उनके पास अत्याधुनिक सूचना तंत्र है लेकिन हमारे सैनिकों के पास , हमारे सीमा सुरक्षा बलों के पास केवल पारम्परिक हथियार हैं । हमारा सूचना तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसी पर आज तमाम प्रश्न चिन्ह लग रहें हैं । आज कई मोर्चों पर पाकिस्तान के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उन तमाम मोर्चों पर भारत को कमजोर, लाचार और विवश बनाने की कोशिश की जा रही है । आपने सुना होगा, तमाम अखबारों में हम रोज़ाना पढ़ रहें हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा जाली नोटों के माध्यम से

हिंदुस्तान की जो आर्थिक संरचना है, उसे कमजोर और खोखला करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। दूसरे जो तमाम कट्टर उग्रवादी और आतंकवादी छोड़े गये, उनके द्वारा एकदम जनूनी, उन्मादक तथा उत्तेजक भाषणों के कैसेट्स हमारे गांवों में पहुंच गये हैं और वहां पर लोग उन्हें सुन रहें हैं और हमारे गुमराह लोग उन उत्तेजक भाषणों को सुनकर उत्तेजित हो रहें हैं और शायद उनके समर्थन में उनके साथ खड़े भी हो रहें हैं। यह सारी चीजें हमें सोचने के लिए बाध्य कर रही हैं कि किस प्रकार हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गयी हैं और किस प्रकार हमारी सेना को विश्व के नक्शे पर कमजोर करके दिखाया जा रहा है। इसके लिए मैं मानीनय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि बार-बार आप कश्मीर का दौरा करते हैं। आप एक बार वहां गये तो आपने सिंधु नदी को नमस्कार किया-यह अच्छी बात है, हमारी सांस्कृतिक गरिमा की बात है लेकिन वहां लेह और लद्दाख के लोग जो आज भी पेयजल से वंचित हैं, स्वच्छ पेयजल से वंचित है, जिनके घरों में बिजली नहीं है, जहां विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, इन बुनियादी और मौलिक चीजों की आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? मैं उनका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा है कि हमारे सुरक्षा बल को अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों अत्याधुनिक सूचना तंत्र और अत्याधुनिक खुफिया तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? इसके अतिरिक्त उन निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं जिन्हें आतंवादियों और कभी हमारी सेनाओं के अत्याचार का सामना करना पड़ता है ? उन अनाथ महिलाओं, उन बेवा औरतों और उन लावारिस बच्चों के पुनर्वास और उनके रोजगार के लिए आपके पास कौन सी योजना है ? कश्मीर की समस्याओं के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने के संबधं में आपका क्या विचार है? सबसे अहम सवाल आपके सामने मैं यह रखना चाहती हूं कि आज तमाम आतंकवादी संगठनों एंव आंतकवादियों से आप बात कर रहें हैं, उन्हें जेल से मुक्त करके बातचीत करनें में आपने पहल दिखायी है।

क्या आपने इस कार्य को करने से पहले यह जानकारी ले ली है कि ये लोग पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरी शक्ति के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित तो नहीं हो रहें हैं ? ये तमाम मुद्दे हैं जो इस हिंदुस्तान की जागरूक जनता आज जानना चाहती है और आश्वस्त होना चाहती है क्योंकि जम्मू-कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारे सिर का ताज हैं और उस ताज पर आज उंगलियां उठ रही हैं, अनेकों लांछन लग रहें हैं,और वह ताज आज इंसान के लहू से लाल हो रहा है। इसलिए यह देश जानना चाहता है कि आज आप जो कुछ करने जा रहे हैं या कर रहें हैं, इससे हमारे इस भारत देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी या नहीं ? धन्यवाद।

4.00 P.M.

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the Home Minister for having offered an opportunity of talks to, what he calls, the alienated members of the society. I have also seen his. statement where he said, 'The doors are open for the Hurriyat Leaders to talk to the Government." As far as I know, so far, no talks have taken place between the two; whatever may be the reports. But a sad thing is that the Hurriyat Leaders, when they were in jail, were treated very badly. Mr. Yasin Malik met me a couple of days ago and complained that he was treated like an ordinary criminal and his sister was not allowed to met him -initially, there was some opportunity, but there was no opportunity later on. I cannot understand; when we have to talk to these people, why do we have to treat them badly in jail? I also wrote to the hon. Home Minister about this. He would recall. Anyway, that is not the issue I am trying to make here. I find from the statement of the Home Minister that again, the emphasis is on force. It is a political issue. It is not a military issue. We have seen that. I agree with whatever he is doing there. But, I think, two more things have to be done there. The first one is, improve the governance. After all, we have one kind of governance, in the whole country; and there, we have a different kind of governance and this has been happening over the last forty, fifty years. We nominate from Delhi who is going to be the Chief Minister there and, when he is not pliable, we decide on some other person; and elections are a farce there. We have never heard of fair elections; fair elections were held only once, and that was in 1977. It is very important that we really know who are the real representatives of the people; and for that, I think, the present Assembly of Jammu and Kashmir should be dissolved and fresh elections be held. That is one suggestion I have.

The second suggestion is this: Yes; any solution has to be within India because there is no question of any solution beyond this country. It is not envisaged. Nor will it be acceptable, but, may be, not within the Constitution. After all, we have amended the Constitution so many times and we are now reviewing the Constitution. If the solution is within India, I personally think, we should try and not insist that it has to be within the Constitution. This is the second suggestion I have.

The third suggestion is this. I think, I would like to share with the House the two thing, which I told Mr. Yasin Malik. I said, "You should go back..." - Now, he has gone back - "...and ask the Hurriyat to announce that it is not a Jehad. Whatever may be your struggle or whatever name you give to it, but it is not a Jehad." He agreed with me saying, "Yes; it is a struggle and it is not a Jehad." The second thing, I said, was: "Whether we like it or not, this State has now been separated into three, zones or regions..."

Jammu wants to join India; pro-Hindu, majority of Hindus; Ladakh, again, wants to be a Union Territory with India, and then you are left with the Valley. Unfortunately, the whole thing has become communalised. I said, "If you really want the whole Jammu & Kashmir, do something to revive that Kashmirian who is away from communalism, which means secularism." I don't know, how much he can do, or, how he will do But, Sir, I have followed the Kashmir woe for the last 40-50 years as a journalist, as a'human rights activist, and in other capacities. There is no doubt that alienation of people is there. There are no two opinions about that. But, I think, we, in the rest of India, have never really tried to understand Jammu & Kashmir. We have thought of it as a territory, as it is our own, and nothing else beyond that. I don't want to go into the history, but if we want to save this State from further conflict, what can we do. There is no doubt in my mind as to what are the intentions of Pakistan. I shall give you one instance. I went to Lahore with Vajpayeeji. There was a breakfast where Shri Prakash Singh Badal, the Chief Minister of Punjab, was present. I was also invited there. Shabaz Sharief, Nawaz Sharief s brother, was then the Chief Minister. He said, "Sardarji, you take the Hindu *ilaka* of Jammu, the Buddhist *ilaka* of Ladakh, and give us the Valley". Shri Prakash Singh Badal said, "जी ये तो ऊपर की बातें है, समझ नहीं आती ।"But, I intervened. I said, "Sir, the fate of Jammu & Kashmir is not going to be decided on the basis of religion. We had enough of religion in 1947. The basis can be anything else, but not religion." I further said, "Do you want to go back to the time of partition - the same bloodshed, the same thing? I have seen how plebiscites are held here. In North Frontier Province, when there was a plebiscite, there was only one appeal - Quarran Sharief or Geeta nothing else." I said, "Plebiscite is always reduced to that." The point I am making, through you, to the Home Minister is that, I think there is a possibility of winning over some elements in Jammu & Kashmir. There is a

possibility of some solution, but, for that, a ground will have to be prepared, for that we have to decide as to how far we are willing to go. For that, are we prepared to say, "Look here, whatever we do, it can be within India but it may not be within the Constitution." Thank you, Sir.

SHRI P.N. SIVA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman. Due to the constraint of time I will not be repeating the observations which have earlier been made by the hon. Members, though they need some repetition. The anti-social elements from outside the country have always tried to disturpt the peace within our nation, to disintegrate the unity, and to stagnate the economic progress. It is no new thing to us, but, at present, as far as this issue is concerned, the attempts our severe and the condition is worse. What should we do at this juncture? Before going into that, I would like to say that first; we have to take into account the sense of the people there. The recent elections which were held in Jammu & Kashmir, were fair and free, and as it was conducted in a peaceful manner, it established the fact that the people there are for a peaceful life, a popular Government. By nature, they are secular; Whatever may be the interpretations of many sections of the country, or anybody else, the people are secular in nature. They are for unity; they are for a peaceful life. Sir, what the Government has to do and what the political parties have to do on their part? Everybody has expressed his opinion. Many Members have suggested that the Government should convene a meeting of all parties. I think it is a very good suggestion and it should be considered seriously. Sir, all the other views and opinions expressed by various hon. Members can be taken into account. Apart from strengthening the security cover across the border, especially, in the areas that are prone to infiltration by the terrorist outfits, the foremost thing in front of the Government is to accelerate the economic development and eradicate unemployment, The Government has to concentrate on these two aspects. Sir, yesterday, when my colleague, Shri Mirza Abdul Rashid, was speaking on the Budget, he was in tears, since he is from the Valley. He was able to express the views and the condition of the people there. Sir, the people of Leh remain employed for only three months and the people of Kashmir remain employed for only six months.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) in the Chair]

Sir, this expresses the situation in the Valley. The reply which the hon. Finance Minister gave yesterday was convincing and what the hon.

Home Minister has said today is consoling. But I think the reply is not such which can satisfy the people of the Valley. So, Sir, through you, I would like to urge upon the Government to concentrate on these two aspects of economic development and eradication of unemployment. Sir, employment and education are inseparable. I would like to know from the Government as to what is the standard of education in the Valley. If at all the situation or the atmosphere there is not conducive for providing education to the children, I would like to know what steps or efforts the Government is making to give education to these children, either outside the Valley, or, within the Valley. Sir, in his statement, the Home Minister mentioned about a number of steps that the Government took there after the post-Kargil phase. I would like to quote one sentence from his statement. It is said, "The aforementioned steps resulted in the killing of approximately 950 terrorists from August, 1999 to April, 2000." But the loss, which has been caused to us on this account, has not been mentioned in the statement. In addition to this, I would like to know from the Government regarding the steps it is going to take to solve the problems of those soldiers and those people who have been affected. Sir, I belong to a regional party, the DMK Party. We are very happy to say that we have got a national outlook and a national interest. We have given an *ex-gratia* amount of Rs. 5 lakhs to the bereaved families of those soliders who have died during the Kargil war. They have been given a flat and employment to one of their family members is also provided. The soldiers who have died in Kargil were all brave patriots. So, providing only *ex-gratia* amount is not sufficient. Priority can be given to the family members of these soldiers in the employment opportunities that the Government is going to create. Their condition is worse. Sir, instead of talking about the existing situation or going into the reasons for all these things, our foremost duty now is to extend our cooperation to the Government, whichever is the Government. Our foremost duty is to bring peace in the Valley. They have lost peace and they are expecting a better future. So, on behalf of the DMK I would assure this House that we would extend all cooperation to this Government for the steps which it is going to take to restore peace and normalcy in the State. We also provide our cooperation to uplift the standard of the people in the Valley. Thank you, Sir.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हैं और मुझे भरोसा है कि जब तक भारत रहेगा तब तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना

रहेगा । इस संदर्भ में मैं देश के बंटवारे की स्थिति को थोड़ा सा उद्धृत करना चाहता हूं । जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय कश्मीर की जनता स्वतंत्र थी कि वह पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेगी या भारत के साथ रहना पसंद करेगी । लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से कश्मीर वासियों को बधाई देना चाहते हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उस समय कश्मीर की जनता के सर्वसम्मति से भारत के साथ रहना स्वीकार किया । कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है और इसी कारण संविधान के अनुच्छेद 370 की विशेष सुविधा भी कश्मीर को प्रदान की गई । लेकिन आज वही कश्मीर आतंकवाद के कारण नरक में बदलता जा रहा है । आज जो भी घटनांए वहां घटित होती हैं, जो भी हत्यांए होती है, आज सहज भाव से देश की सरकार की ओर से गृह मंत्री की ओर जो बयान दिया जाता है कि यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण हैं या इसमें आई.एस.आई का हाथ है । मैं समझता हूं कि अपनी कमजोरियां को छिपाने के लिए इस प्रकार की बयान अक्सर सरकार द्वारा किया जाता है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर हमारा लड़का नालायक निकले तो हम यह कहें कि पड़ोसी के लड़के के कारण हमारा लड़का नालायक रहा है, यह बात उचित नहीं होगी ।हमारी किसी न किसी कमी के कारण हमारा लड़का नालायक हो रहा है । इसलिए मैं मंत्री जी चाहता हूं कि हमारी शक्ति को इतना मजबूत करना चाहिए, खुफिया एजेंसी को इतना मजबूत करना चाहिए कि आई.एस.आई. और पाकिस्तान के आतंकवाद को एकदम चूटकी से मसल देने की जरूरत है । मंत्री जी का जो बयान आया है, उसके अनुसार अगस्त, 1999 से अप्रैल, 2000 तक लगभग 950 आतंकवादी मारे गये हैं । मैं मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या यह सारे लोग जो मारे गये हैं । उनकी पहचान कर ली गइ है और यदि पहचान कर ली गई है तो उसमें पाकिस्तानी कितने रहे और कितने बेकसूर कश्मीरी मारे गये ? क्या इस प्रकार की शिनाख्त की गई है । आज सब से अहम सवाल है कि आतंकवाद के कारण का पता लगाया जाए क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं लगाया जाएगा उसका निवारण नहीं किया जा सकता है । आज देश के कुछ हिस्सों में बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर से 370 हटाओ और हटाने की धमकी दी जाती है । मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन से लोग हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? इसी तरह से बेरोजगारी के कारण वहां आतंकवाद बढ़ रहा है भुखमरी के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है आज अधिसंख्य हिंदूवादी क्षेत्रों से कभी कभी आवाज़ उठाई जाती है कटुआ काटा जाएगा तो राम राम चिल्लाएगा । मुल्लाओं के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान । क्या यह कश्मीर में आतंकवादी को बढ़ावा देने के कारण नहीं हैं, इन सब कारणों का निवारण करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? मैं अंत में सभी देशवासियों से और राजनीतिक दलों से अपील करना चाहता हूं कि राजनीतिक स्वार्थों से

ऊपर उठ कर के हमें आतंकवाद से निपटने के लिए आज मिल-जुल कर के देश को मजबूत बनाने की जरूरत है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Shri Sharifulla Sharief.

SHRI SHARIEF-UD-DIN SHARIQ (JAMMU AND KASHMIR): I am Sharief-Ud-Din Shariq. I do not know why my name is always misread.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I would have loved to answer you.

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफ: अब तो हो गया जो हो गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोड़कर): मैं माफी चाहता हूं।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Whatever is done is done. You cannot undo it.

*__श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफ :__ जनाबे सदरेनशीं। बहुत दिलचस्प बहस हुई कश्मीर के बारे में और इस बारे में जो ख्यालात जाहिर किए गए, इस सिलसिले में जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा है हदबजानिब है क्योंकि जिस्म का एक हिस्सा अगर दुखता है तो सारे जिस्म को तकलीफ महसूस करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो कश्मीर के पशेमंजर से नावाकिफ हैं उन्होनें भी बड़ी बड़ी बातें कीं और अलग जाकर उनसे पूछूं तो उनको कुछ मालूम नहीं होगा। चंद अखबारी इत्तिलाहाद पर, चंद मालूम पानी सुनी सुनायी बातों पर कहानियां बनाना सियासी जानिबदारी नहीं है। कुलदीप नैयर साहब बहुत ही पुराने लोग, बहुत ही तजुर्बेकार है और कहा 1947 से मैं बाबस्ता हूं लेकिन इतना भी मालूम नहीं कि वहां जो इलेक्शन हुआ, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में

हुआ ...(**व्यवधान**)... सुनिए, मुझे नहीं मालूम। आइन में कितना लिखा है, पढ़ना चाहिए। वह भी मैं बताऊं कि कितना पढ़ना चाहिए। पर आपने फटाफट यह हुक्म दिया कि वहां की सरकार को और असेम्बली को डिसमिस कर लो। यह कश्मीर के लोगों की आपने तौहीन की है जिन्होनें10 साल तक गवर्नर राज में पिसकर पहली बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एक जम्हूरी हुकूमत कायम की, एक ऐसे लीडर को कायम किया जो सारे देश की नाक है और जेनेवा जाकर पाकिस्तान के अजाइन को फाश करता है, इसका आपको कोई अहसास नहीं है। आप उनकी वकालत करतें हैं जिन्होनें सड़क पर बेगुनाह एयरफोर्स के चार

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

अफसरों को गोली मारकर उड़ा दिया और आज उनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में हैं। आप उनकी वकालत करते हैं जिन्होनें मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की ...(**व्यवधान**)...

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, it is not fair. *(Interruptions),* रिबट करने का मुझे हक है

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please sit down.

SHRI KULDIP NAYYAR: You cannot say I am supporting violence.

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफ : मोहम्मद सईद की बेटी को जिसने अगवा किया और उसने कहा कि मैनें अगवा किया है उसकी आप वकालत कर रहें हैं। व्हाट एल्स? कश्मीर के पशेमंजर से वाकफियत होने का दावा आप कर रहे हैं। मैनें कोई सच्चाई नहीं पी ली है।

कश्मीर को बांटने की बातें की। किसी ने कहा, जनरल चौधरी साहब ने कि कश्मीर का वह जो हिस्सा है उसको हम लाएंगे। ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। हम जिस जमीन पर यह रहें हैं उसमें हम पिस रहें हैं। हम और आप यहां दिल्ली में तकरीरें कर रहें हैं। हमारी बेटियां मर रही है। हमारे भाई मर रहें हैं कश्मीर में। तकरीरें करना बहुत आसान बात हैं। वहां हिंदु दरबदर है, परेशान है, मुल्क में घूम रहा है, भिखारी बन रहा है। जो इंटेलीजेंट था, जो प्रोफेसर था, जो डाक्टर था, वह भीख मांगने पर मजबूर है। मेरा मुसलमान मर रहा है और आप सियायतबाजी करेंगे यहां, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे।

हमने कश्मीर दिया है हिंदुस्तान के साथ। मुसलमानों ने दिया है। शेख अब्दुल्ला ने दिया है। महाराजा हरी सिंह ने दिया है। जब यहां के लोग एक दूसरे का गला काट रहें थे, जब ट्रेनों में लाशें ही लाशें दौड़ रही थी सियालकोट से लाहौर और यहां दिल्ली तक उस वक्त महात्मा गांधी कश्मीर में आए और देखा कि हिंदू मुसलमान गले मिल रहें हैं। तो उन्होनें कहा कि मुझे रोशनी की किरण सिर्फ कश्मीर में नजर आ रही है। यह एक तवारीख है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह हिस्ट्री है।

किसी ने यह सुझाव दिया कि लद्दाख वाला कहता है कि इधर आओ। जम्मू वाला कहता है इधर रहो। कश्मीर वाला नहीं कह रहा है। लद्दाख वाले ने नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ मिलूंगा। जम्मू वाले बेचारें ने उस वक्त भी नहीं कहा, कश्मीर वाले ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के साथ चला जाऊंगा। आज के आतंकवाद का हीं नहीं, 1947 से लेकर आज तक

कश्मीर ने हर उस चीज का मुकाबला किया जहां मुल्क की आन, मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात चली । आज पसपरदा हम पर शक अगर आप लोग करेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे । मैं दिन दहाड़े चैलेंज करके इस बात को कह रहा हूं । हमने कहा कि हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा मुस्तकबिल,हमारी जिंदगी इसी मुल्क में हैं । यह हमारा एलान है और हमेशा के लिए है । यहां तज़वीज़े देने वाले लोग आते हैं । यहां बढ़िया ऐसी तज़वीज़ दे दो । हमने दिया है, आप संभालों, कैसे संभालते हों । क्यों नहीं संभाल पाते ? क्यों मिलिटेंट बॉर्डर क्रॉस करते हैं । क्या तारों की बाड़ बॉर्डर पर नहीं हैं? वहां फौज आपकी हैं, आपकी पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं । क्यों हजारों लोग आते और जाते हैं ? उनको कौन छोड़ता है ? यह सियासी फैशन चला है । अपनी सियासत का बालादस्ती को काला करके मुल्क के मफाद को कोई नज़र में नहीं रखता । आप संभालिए । जब कांग्रेस के शिकम से, पेट से, पहलू से मुस्लिम लीग बनी तो मुल्क तकसीम हो गया और हम मुस्लिम कांफ्रेंस के पहलू से जन्म पाकर नेशनल कांफ्रेंस बनाए हैं । हमारी बिल्कुल उल्टी बात है।

जनाब-ए-सदन नशीं, क्योंकि जज़बाती मामला है, मैं थोड़ा जजबाती हुआ हूं, इस पर मुझे मुआफ किया जाए । मुल्क को तकसीम हमने नहीं किया, फारूक अब्दुल्ला ने नहीं किया, कश्मीर के मुसलमान ने नहीं किया, महात्मा गांधी ने किया है । दोष उस पर दे दो । आपने किया, मजहब के नाम पर किया । हमने नहीं किया । हम उस वक्त भी हिंदु-मुस्लिम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे । पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया तो हमारे लोग डंडा ले कर, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार और नारे लगाते थे, शेरे कश्मीर का क्या इरशाद,हिंदु-मुस्लिम-सिख इत्तिहाद । यह हमारा कलमा बना था । हमारा ईमान था । हमें कोई पैसा नहीं देता था इसके लिए । आज चावल की बोरी का भी हमारे साथ हिसाब लगाया जाए और जब हम पैसा मांगे तो कहा जाए कि नहीं है । लाखों नौजवान हैं । आप अपने बेटों का ख्याल कीजिए । हर पार्टी से और सारे देश से मेरी यही अपील है, एम.एस.सी.बायोकैमिस्ट्री किए हुए लड़का घर में बैठा है । सुबह-शाम कोई काम ही नहीं । टीवी खोलता है तो पाकिस्तानी टीवी उसको कहता है कि जेहाद करो । मेरा टीवी कहता है कि यहां पर कोई नौकरी ही नहीं हैं । वह कहां जाएगा ? आपके फैसले मैं आप पर छोड़ता हूं । वहां 6 महीने सड़क बंद है, बर्फ से बंद रहता है, कट जाता है । मैं कहता हूं कि मुझे सड़क दे दो, उसको देश के साथ मिलाओ, इंटेग्रिटी ज्यादा बढ़ाओ । आप कहते हैं कि पैसे नहीं है । वह कहता है कि मेरे पास भी तुमसे मिलने की फुर्सत नहीं है । मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल एअरपोर्ट मुझे दे दो । पता नहीं उस पर ब्यूरोक्रेट वहां क्या-क्या लिखतें हैं, मुल्क को शदीद खतरा है अगर वहां पर इंटरनेशनल एअरपोर्ट बना । आप हमको फ्रस्ट्रेट करते हैं । आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हमको ताव्वुन दीजिए । मिलिटेंसी आप नहीं, हम खत्म कर देंगे लेकिन ताव्वुन तो दीजिए। मिलिटेंट लीड़र्ज़

के खिलाफ हम लड़े । आपके हुर्रियत वाले अगर हैं, आपने कहा असेंबली डिसमिस कर दो । कर लो, हम इलैक्शन के लिए तैयार हैं । हम असेंबली डिसमिस कर देंगे । आप इलैक्शन के लिए उनको तैयार करो, अगर उनमें दम हैं । मस्जिदों में मजहबी तकरीरें करना अलग बात है, जमीन पर पब्लिक के सामने हकीकत बर्दाश्त करना अलग बात है, मै आपसे गिला नहीं तो चैलेंज करता हूं, वे आयेंगे हमारे साथ इलैक्शन में तो वे कितने वोट पाएंगें । उस वक्त आप अपने याद-दोस्त ले करके आब्ज़र्वर बनायेंगे और देख लीजिए, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक । ये कहने की बातें अलग हैं । उन्होनें आजमाया है । पचास साल तक हमारे साथ वे लड़े हैं । अब पाकिस्तानी का पल्लू पकड़ लिया । वहां का बंदूक लाया, वहां का ग्रेनेड फैंका । मेरे घर को आग लगा दी । वह अलग बात है । यह फॉल प्ले है । यह कोई जायज़ बात थोडें ही हैं ।

जनाब-ए-होम मिनिस्टर, आपसे गुजारिश है इनके थ्रू और सारे एवान के थ्रू, जैसा इन्होनें कहा मसला पोलिटीकल है, उन्होनें अटोनॉमी की बात की, वह ऐसे पेश किया जैसे कुछ तबाही हो रही है और अटोनॉमी से दो मुल्कों को नुकसान हो रहा है । हम विदड्रा कर लेंगे, कोई अटोनॉमी की जरूरत नहीं है । पहले मुल्क की सालमियत, बाकी बातें बाद में । 1947 से लेकर 1968 तक .....। जब तक बख्शी गुलाम मोहम्मद वहां प्राइम मिनिस्टर थे,उतने दिनों तो आटॉनोमी बहुत चल रही थी वहां उस से कुछ नुकसान नहीं हुआ । अगर आज मुख्तलिफ रीजंस के लोगों को शिकायत है, जम्मू वाले को शिकायत है कि कश्मीर वाले की मुझ पर बालादस्ती है, मैं कहता हूं कि उस को भी अपना अधिकार दे देंगे पावर में । लद्दाख वाले को शिकायत है, उस को कहते हैं आप को भी इंटरनल आटोनॉमी चाहिए और कश्मीर वाले को लगता है कि वह शायद मुझे खा जाएंगे तो उस को भी ऑटोनामी हो ।

उपसभाध्यक्ष(श्री अधिक शिरोड़कर): शरीफ साहब, आप के 5 मिनिट के बदले10 मिनिट हो गए हैं ।

श्री शरीफ-उद्-शरीफ : मैं खत्म कर रहा हूं और यह भी जान लीजिए कि कश्मीर एक सेंजुटा जगह है, मेजॉरिटी मुसलमान रियासत केवल एक है इस देश में और गर्व होना चाहिए इस देश को भी, देशवासियों को भी । जब यहां फिरकावाराना फसादात हो गए तो तास्सुरर जरूर वहां चला जाएगा । उस चीज को खत्म कर दीजिए । खत्म कर दीजिए पुरानी बातें । हम भारत को नया बनांए, बहुत खूबसूरत जेहनतदार भारत और मजबूत भारत बनाने की कोशिश करें जो मजहबी बुनियादों पर और सियासी नारेबाजी पर नहीं बनना चाहिए । ऐसा भारत बनाएं, इन्शा अल्लाह ....**(समय की घंटी)**... और जब तसलसुल से मैं बात करना चाहता हूं तो मेरे पास वक्त नहीं है । हम तसलसुल से बात करें तो 53 में शेख मोहम्मद

अब्दुल्ला को रातों-रात गिरफ्तार कर के जेल में बंद किया गया और कश्मीर में एलिनेशन आ गयी । उन के प्यारे रहनुमा, जिस ने उन के लिए सारी जिंदगी जी थी, दिल्ली में साजिश बनायी और यह चीज भी जमा हो गयी । फारूख अब्दुल्ला की सरकार को मेजॉरिटी होते हुए खत्म किया गया और सारी दुनिया का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया, भिंडरावाले से मिलकर साजिश करने तक का इल्जाम उस पर लगाया गया, यह सारे तसलसुलात जब देश में हुए तो मिलिटेंसी के रूप में ब्लास्ट हुए । जब नफरतें आएंगी, जब बेएतबारियत आएगी, जब एतमाद कम हो जाएगा तो यही होना है चाहे कश्मीर हो, चेन्नई हो या और कोई जगह हो । आज मुल्क में रियासत में लोगों के ऐतबार को बहाल करने की जरूरत है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोड़कर) : शरीफ साहब, 5 मिनिट के बजाय 12 मिनिट हो चुके हैं ।

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफः लिहाजा रियासत में इस हाऊस को, इस हुकूमत को वहां की जो मुन्तख़बा सरकार है, उसे पूरा समर्थन देना चाहिए, पूरा विश्वास देना चाहिए, माली पूरी उम्मीद करनी चाहिए ताकि वह तमाम उन शिकायत का इजाला करे जो वहां के नौजवानों की, और लोगों की जो मुश्किलात हैं उन को दूर करें और यकसुई के साथ मिलिटेंसी को खत्म कर दे, मिलिटेंसी के खिलाफ लड़े । उन तमाम सियासी मशविरों को सामने रख ले जो रियासत की ऑटानोमी के सिलसिले में दिए जा रहें हैं । उन पर गौर कर लें, गौर करने मे कोई गुनाह नहीं है ।

मैं आपको मुबाकरबाद देता हूं होम मिनिस्टर साहब, मैं ने अखबार में पढ़ा कि आप ने तीन सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनायी है उस रिपोर्ट पर गौर करने के लिए और जैसा कि हुर्रियत कांफरेंस के लोगों के बारे में कहा गया है और इन्होनें इलेक्शन की बात फरमायी कि एसेंब्ली की तोड़ दीजिए । मैं इनकी हिमायत करता हूं वह आएं एसेंबली तोड़ने के लिए और लड़े इलेक्शन हमारे साथ,कर लें हमारी आइन पर एक बार फिर दस्तखत । हमें एतराज नहीं, वह हुकूमत भी चलाएं उन का हक बनाता है। हर हिंदुस्तानी का हक है कि हुकूमत में आ जाए, सत्ता में आ जाए, कुर्सी पर आ जाए । इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन कत्ल और सियासत, इगवा और सियासत, बम-ब्लास्ट और सियासत-ये दोनों शायद इकट्ठी नहीं चल सकती । आखिर में एक शेर अर्ज करूंगा ।

आज वह कश्मीर है महकूमों-मजबोरों फ़कीर,
कल जिसे पहले नजर कहते थे ईराने सगीर ।

खुदा हाफिज़ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोड़कर): धन्यवाद शरीफ जी। मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी। आपके भी 5 मिनिट हैं।

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी :** बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत हैं 5 मिनिट आप की मेहरबानी। सदर साहब, मसला-ए-कश्मीर पर एक बहुत ही तफसीली और सुलझी हुई बहस, मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामेंट में हुई जिस का आगाज मेरे मोहतरम् जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े सलीके से कर के पूरे मुल्क का एहसास

जगाया है बल्कि मैं यूं कहूंगा कि एक यह ऐसी आजाद नज्म है जिस का उन्वान गुलाम नबी आजाद साहब बने और जिस का बहुत अच्छा शेर शरिक साहब ने ... और जिसका बहुत अच्छा शेर शरीक साहब ने बनकर देशवासियों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। मैं पांच मिनट में अपने जज्बात का इज़हार भी एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते करना चाहूंगा।

कश्मीर, जिसमें लाल-ओ-गुल की बहार थी

आतंकवाद की वहीं आंधी भी आ गई

झरनों की लय पे गाती हुई चलती थी हवा

रंगे चनार में थी वहीं मौसमों की आग

और केसर की बू में हिंद के इतिहास का सुरूर

उस सरज़मीं पे आज है बारूद का गुरूर

अलगाववाद, खून-खराबे का जोर है

इंसानियत सुलगती है, जहलुम का शोर है

डल झील में अब बर्फ नहीं, सिर्फ खुन है

सरकार ही बताए यह कैसा जुनून है।

---

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate

शुक्र है कि कश्मीर के मसले पर बहुत तफसीली बहस हुई , वरना हम लोग यह सारी खबरें रेडियो से, टेलीविजऩ से और अखबारों के जरिए हासिल किया करते हैं । मसाइल जहां तक कश्मीर के हैं, कश्मीरी मुसलमान यकीनन काबिले मुबारिकबाद है जिसने कश्मीरियत को हिंदुस्तान के साथ वाबिस्ता रखने के लिए महाराजा कश्मीर से लेकर हिंदुस्तानी हुकूमत तक अपने ऐतमाद का इजहार हर दौर में किया है । कश्मीरियों ने अपने इस नादिर-ओ-नायाब फैसले के जरिए ने सिर्फ यह है कि कश्मीर की इजाजत हम तमाम हिंदुस्तानियों के दिलो-दिमाग में बढ़ाई बल्कि खुद कश्मीर और कश्मीरियत में, महाराजा कश्मीर से लेकर के मुसलमानों तक सारे राजा और प्रजा की पुरानी कहानियों को सैकुलरिज्म की रवायात में दोहराते हुए हिंदुस्तान के सैकुलरिज़्म को चार चांद भी लगाए । आज जिन मासाइल से कश्मीर के आवाम गुजर रहें हैं, यकीनन वे बड़े हस्सास मसाइल हैं । हिंदुस्तान के साथ उन्होनें जीने और मरने का फैसला किया । इसी मुल्क की मिट्टी में कश्मीरी सुपुर्दे खाक भी होता है, इस मुल्क से अलग होने का कश्मीरी तसव्वुर भी नहीं रखता । शरीफ साहब ने उसके बैकग्रांउड को बहुत तफसील के साथ अपनी तकरीर में बतलाया है. जिससे हम लोग काफी मुतास्सिर भी हुए हैं ।

सर, मैं सिफ दो-तीन बातें कहना चाहूंगा । जहां यह हकीकत है कि कश्मीरी मुसलमान ने पाकिस्तानी मुसलमानों को और पाकिस्तान जैसे देश को छोड़कर हिंदुस्तान के साथ अपनी जिंदगी और मौत को वाबस्ता किया, आखिर क्या वजह है कि आज वही कश्मीर बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है । आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में इतनी बड़ी बेइत्मीनानी है कि हमारी विशाल मुल्क् फौज का बड़ा हिस्सा कश्मीर के अंदर लगाए हुए हैं । बार्डर सिक्युरिटी फोर्सिस भी हमारी वहां मुस्तैदी से काम कर रही है, पुलिस भी वहां मौजुद हैं,मगर मरीजें इश्क पर रहमत खुदा की, अर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । जितना की ज्यादा मसाइल को तय करने की हमने कोशिश की उतना ही ज्यादा हमारे मुल्क के साथ छेड़छाड़ करने में आतंकवादी कामयाब होते चले गए । ये बातें उमूमी तौर पर कही जाती है और सच्चाई भी है कि जब हाथों को काम नहीं मिलेगा तो वे हाथ अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कहीं न कहीं से अपने माद्दी सामान को हासिल करने की कोशिश करेंगे । मगर जिन कश्मीरियों का ऐतमाद पर ऐतमाद लोगों को क्यों नहीं हो रहा । बातें बड़ी साफ-साफ कही गई है,इसलिए मैं भी एक बात साफ तरीके से कहना चाहता हूं । मैनें जाड़े के जमाने में देखा है कि उन कश्मीरियों को पकड़कर पुलिस बंद करती है, उन कश्मीरियों को पकड़कर उनकी चादरें उनके सामान छीन लिए जाते है, पटना में भी यह घटना हुई, दिल्ली में भी यह घटना हुई । मैने बहुत बुरी तरीके से इस घटना को महसूस किया है । कश्मीरियों को प्यार के साथ अपनाने

की जरूरत है, कौमी धारा में उन गुमराह लोगों को लाने की जरूरत है जिन लोगों को आज पाकिस्तान ने मुकम्मिल तौर पर ट्रेनिंग देकर , बार्डर के उस पार से अपने आतंकवादियों और हमलावरों को भेज-भेज कर हिंदुस्तान के अंदर अशांति फैला रखी है। जरूरत तो यह थी कि कोई कश्मीरी मुल्क के किसी हिस्से मे जाता,चाहे वह हिंदु होता है मुस्लिम होता, सर, आखिरी बात कह रहा हूं, उस पर ऐतमाद किया जाता , उसके साथ सहानुभूति जताई जाती, उसको अपना बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती, उसकी रक्षा-सुरक्षा के लिए काम किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शक के बादल छाते हैं और शक का लहू बरसाया जाने लगता है। इसलिए मैं होम-मिनिस्टर साहब से तकरीर न करते हुस सिर्फ चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। वहां की रियासत गरीब है, सभी लोग जानतें हैं। वहां जो कुछ भी पैसा भेजा जाता है, जैसे और सूबों के लिए हम पैसे आवंटित करते हैं, उसी तरह से वहां भी हम पैसे भेजते हैं, कोई खास मखसूस पैकेज हम वहां नहीं भेजते हैं और वहां के लोगों की इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है जितनी बड़ी समस्या बिहार में हैं या यू.पी.में हैं जितनी बड़ी समस्या दूसरे सूबों मे हैं, इसलिए कि उन सूबों में लोग ज्यादा है, वहां अवाम करोडों की तादाद मे हैं और जहां लाखों की तादाद में लोग हों, उनके मसायल को हल करना और ऐसे माहौल में हल करना जब कि एक विदेशी मुल्क पाकिस्तानी उनको उचके लेना चाहता है, कोई मुश्किल काम नहीं है।

महोदय, पाकिस्तान की बुनियाद ही हिंदुस्तान से दुश्मनी पर पड़ी हुई है। पाकिस्तान जिस दिन से आलम-ए-वजूद में आया है,पाकिस्तान का वन प्वाइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान में कमजोरी पैदा करो, हिंदुस्तान के लोगों को नफरत के साथ बाटों, इनके अंदर मंदिर और मस्जिद के झगड़े पैदा करों, हिंदु-मुसलमान के झगड़े पैदा करों, हमेशा अदमे-इस्तेहकाम की पोज़ीशन में हिंदुस्तान को रखो और हिंदुस्तान को तरक्की की राहों पर चलने का कोई मौका न दिया जाए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारी तकदीर का फैसला करने वाला मुल्क नहीं है। हमारी अवाम ही हमारी तकदीर का फैसला करेगी। पाकिस्तान अगर अदमे-इस्तेहकाम पैदा करता है तो हमें बहुत ज्यादा चौकस होकर मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा चौकस होकर आपस में तमाम पीपुल्स की इकाइयों को मुत्तहिद करके हिंदुस्तानी की शक्ल में खड़ा करना चाहिए। मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है।

इसलिए मैं होम-मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि जो पैसा वे वहां भेज रहें हैं, वह पैसा तो वहां की पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ के ऊपर खर्च हो रहा है, वह पैसा वहां की पुलिस पर खर्च हो रहा है। वहां की गरीब अवाम के मुंह तक वह निवाला क्यों नहीं जा रहा है ? वहां

के गरीब लोगों तक वह चीज क्यों नहीं पहुंच रही है ? वहां के लोगों की तालीम के लिए रास्ता क्यों नहीं पैदा हो रहा है ? वहां की रोड्य क्यों नहीं बन रही है? महोदय, बर्फ पिघलने के बाद वहां का आदमी किस लाचारी में, मजबूरी में अपनी जिंदगी गुजारता है, उससे आप वाकिफ ही है । इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचाने की जरूरत है ।वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐतमाद में लाने की जरूरत है । मैं होम-मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता नही निकाला जा सकता है कि वहां के नौजवानों को गुमराह करने वाले लोग उनके हाथों में बंदूके दे देते हैं, हम उनके हाथों में काम दे दें ? हम पूरे मुल्क में उन कश्मीरियों को फैलाएं । यह केवल एक-दो लाख लोगो का मैटर है । मैं नहीं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोगों का मैटर होगा । अगर उनको पूरे मूल्क में आप फैला देते हैं, सारी जमातों के साथ उनकी रोजी-रोटी का हिसाब लगा देते हैं तो यह मसला हल हो जाएगा । हमारे यहां तो दुनिया भर की कंपनियां हैं । अब तो आपकी कृपा से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस मुल्क में अपना काम कर रही हैं । मैं कंपनियों की बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई थी और पूरे देश का सौदा करके चली गई । खुदा खैर करे, अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, मालूम नहीं क्या-क्या होने जा रहा है । बहरहाल, हमें चौकस रहना चाहिए और होम-मिनिस्ट्री को इन सब बातों पर खुसूसी तौर पर नजर रखकर इन तमाम ज़जबात का अहसास करते हुए इसका समाधान निकालना चाहिए । मुझे यकीन है कि होम –मिनिस्टर साहब कोई ऐसा लाहे-अमल जरूर तय करेंगे जिसमें कश्मीरियों को कौमी दायरे में मजबूती के साथ जोड़ा जाए और इस मुल्क में जात, बिरादरी, दीन-धर्म के नाम पर नफरत का खात्मा करते हुए लोगों को खुशहाली की राह पर लगाया जाए । धन्यवाद ।

SHRI SURESH A KESWANI (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I won't take much time of the House because I know that you are already short of time. I am not going to repeat most of the things which have already been said here. Everybody has agreed that Kashmir is a very serious issue. Everyone also realises that the Kashmir issue cannot be solved by wars. It cannot be solved by any other means, except through negotiations. We have also categorically said that there shall be no negotiations till such time the kind of measures which are being initiated from across the border are stopped. In other words, we have taken a stand on Kashmir where the situation is just drifting. We are not realising or grasping what the overall scheme is . Our ex-chief of Army Staff said that this was nothing but a proxy war. The proxy war is being fought not only on the border of Kashmir, within that territory, within the State of Jammu and Kashmir, but it has also extended to the North-East. I am

afraid, it is gradually getting into our backwaters. Sir, a situation is developing in Sri Lanka. We know very well that the options which are available to the Sri Lankan forces are either they will get the help of the US troops or the Israeli troops or the Pakistani troops because we have already declared that in view of our past experience we are not going to do what we had done earlier. I would like to know from the Government whether the ban on the LTTE which is expiring on the 14fh May, is going to be extended. If it is going to be extended, when is it going to be extended and for how long? Shri Vaiko has made a statement that the Tamil people in Sri Lanka need to be supported and we must help them establish.... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Keswani, I am sorry. We are discussing only the Kashmir issue. Please don't enlarge the issue. You cannot refer ..... *(Interruptions).* Please allow me to speak. You have referred to the name of an hon. Member who is a Member of the other House. You cannot do so. Kindly don't enlarge the issue.

SHRI SURESH A KESWANI: Sir, I am making my point. I am not interested in naming any person. I am only saying that in the South we are going to develop a situation where Pakistan may find an opportunity to create another proxy war. This is going to happen there. How is the Government going to respond to this situation? Are we going to support the creation of ....

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR) :Mr. Keswani, please confine yourself only to the problems relating to Kashmir. Don't bring any other issue into it.

SHRI SURESH A KESWANI: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to point out that the enemy that we have across the border is not content with allowing a situation to rest in the drift.level in which it is today. He is active in other areas. How is the Government going to respond to it? We know it very well.

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Sir, these issues can be raised on some other occasion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) :Mr. Keswani, please don't digress; otherwise, I will be compelled to see that all

your statements are expunged. Please don't do it.

SHRI SURESH A KESWANI: Mr. Vice-Chairman, Sir, you have always been very kind to me. I am sure you would not do such a thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): That is why I said, "I will be constrained to do that."

SHRI SURESH A KESWANI: Sir, the purpose of my raising this issue is onry to bring to the notice of the House the seriousness of the situation . How are we going to address the issue of Kashmir? It is going to have repercussions everywhere. What the Pakistani forces want to do is, they want to fight with us on all the fronts. As somebody has said earlier, proxy war is a reality. We cannot ignore that reality whether it transpires in the North-East or in the Sri Lankan waters. Thank you.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आज़ाद का बहुत आभारी हूं जिन्होनें यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर इस सदन को चार घंटे तक जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति पर विचार करने का अवसर दिया। उस दूसरे सदन में तो मांगों पर चर्चा होती है और कई वर्षों बाद गृह मंत्रालय की मांगों पर भी चर्चा हुई थी और वहां पर, चाहे गृह मंत्रालय के दायरे में बहुत सारे विषय आते हैं, अधिकांश चर्चा का केन्द्र बिंदु जम्मू-कश्मीर ही रहा। मैं आभारी हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होनें इसमें भाग लेकर – विशेषकर आखिरी में जब श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफ बोले और आज़मी साहब बोले तो लगा कि देश को और दुनिया को समझना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर का सवाल हिंदु-मुसलमान का सवाल नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर 53 साल की आजादी के बाद भी पाकिस्तान का नज़रिया जम्मू-कश्मीर के बारे में वही है, जो 1947 में था। इसका कारण यह है कि वह देश की आजादी और उसके साथ जुड़ी हुई बातों को हिंदु-मुसलमान के फर्क के अलावा और किसी नज़रिए से देख सकने मे असमर्थ है It is their failure to reconcile with the fact. विफलता है उनकी इस बात से रीकंसाइल करने के लिए कि चाहे विभाजन का आधार अंग्रेजों ने मान लिया हो हिंदु बहुमत कहां है, मुसलमान बहुमत कहां है और चाहे पाकिस्तान ने विभाजन के बाद अपने को एक मज़हबी राज्य घोषित किया हो, हिंदुस्तान ने अपने को मजहबी राज्य घोषित नहीं किया, उसको अस्वीकार किया और उसमें भी विशेषकर जम्मू-कश्मीर की जनता ने मजहबी राज्य की कल्पना को स्वीकार ने करते हुए भारत के साथ अपना विलीनीकरण स्वीकार किया। इस तथ्य के साथ इस ऐतिहासिक सच्चाई के साथ पाकिस्तान रीकंमसाइल नहीं कर पा रहा है और उसमें से ये समस्यांए उत्पन्न हुई हैं।

अब अनेक सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर की समस्या राजनीतिक समस्या है । उसका कोई सैनिक हल नहीं है । हां, सैनिक हल नहीं है,इसमें कोई शक नहीं है लेकिन किसी को इस बात से शिकायत थी कि राजनीतिक समस्या होते हुए भी इसमें सुरक्षा का जिक्र ज्यादा है ।

[श्री सभापति पीठासीन हुए]

यहां एक विचार यह प्रकट किया गया और अनेक सदस्यों ने कहा कि यह राजनीतिक मसला है, it is a political issue, वहां मैनें शंकर राय चौधरी जो कि सेना में रह रहें हैं, उनके इस बयान को भी देखा कि उन्होनें तो इस मोशन पर ही एक प्रकार से अपनी रिजर्वेशन प्रकट की कि आप इस समस्या को इंटरनल सिक्योरिटी के साथ क्यों जोड़ रहें हैं? यह तो एक्सटरनल सिक्योरिटी का मामला है और सही बात है कि जम्मू-कश्मीर के डेवलपमेंट से 1971 के बाद, 1971 से पहले नहीं, 1971 के बाद इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटरनल सिक्योरिटी की सीमा रेखा को लगभग समाप्त कर दिया है । मैं नहीं जानता हूं कि कितनी बार इससे पहले इतनी मात्रा में गृह मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय का इतना इंटरैक्शन होता होगा, मैं नहीं जानता हूं । कम से कम मैं इस सरकार में अभी-अभी आया हूं और इन दो सालों में अगर किसी मंत्रालय से सबसे अधिक इंटरैक्शन होता है तो वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री से होता है । इस सच्चाई को हम समझे, पहचानें और इसलिए 1971 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, जो नए आयाम आए हैं,उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ।

हमारे गांधी आज़ाद जब आखिर में बोल रहे थे तो मैं थोड़ा हैरान हुआ । इनके हिसाब से तो आई.एस.आई.की चर्चा करना बिल्कुल फिज़ूल है, दोष तो सारा हमारा ही है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को हम पहचानें की 1971 के युद्ध में जिस प्रकार की पराजय पाकिस्तान की हुई उसी में से जन्म हुआ है इस प्रॉक्सी वार का । इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और दुनिया को भी नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि प्रॉक्सी वार का जन्म उसमें से हुआ और प्रॉक्सी वार लड़ना सीधे युद्ध लड़ने से ज्यादा कठिन है ।

गुलाम नबी आजाद जी का भाषण मैं सुन रहा था । उनके हिसाब से तो जैसे जो कुछ सत्यानाश हुआ है, इन दो साल में ही हुआ है, बाकी तो ठीक-ठाक चल रहा था, सारी स्थिति सुधरी हुई थी । 1991 से लेकर 1996 तक इतना परिवर्तन हो गया था, 1991 में गड़बड़ की, 1990 में गड़बड़ की, जो उस समय की सरकार थी, जिस सरकार का हम समर्थन कर रहे थे, इसलिए हम अपराधी हो गए उसके लेकिन 1991 से 1996 में

इन पांच सालों में तो बस सब ठीक-ठाक हो गया । इतना ठीक-ठाक हो गया कि उसकी कसौटी यह है कि 1996 में चुनाव हो गए । चुनाव तो 1998 मे हुए, 1999 में भी हुए और परसेटेट भी अच्छा-खासा गोल किया, जैसा इन्होनें बताया । कुलदीप साहब, यह कहना ठीक नहीं है- 1977 के चुनाव का मैं भी क्रेडिट लेता था लेकिन यह कहना कि उसके बाद कोई चुनाव हुआ ही नहीं, हमारे यहां हिंदुस्तान भर में जो चुनाव होते हैं उनमें कमियां तो रहती है । मैं नहीं कहता कि उनमें इररेगुलरीटीज नहीं होती । लेकिन कुल मिलाकर जम्मू-कश्मीर मे हम चुनाव सही करवाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं । इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर होता है । पहले चुनावों मे इलेक्शन कमीशन नहीं होता था, अब होता है । गुलाम नबी आजाद जी की एक बात से मुझे थोड़ी शिकायत है और यह बोला जाता है हमे यह भी समझना चाहिए की जम्मू-कश्मीर के बारे में इस सदन में जो कुछ बोला जाता है वह केवल हिंदुस्तान में नहीं सुना जाता बल्कि दुनिया भर में सुना जाता है, और उसमें हम जहां एक और कहें कि सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, वही हमें पुलिस नहीं चाहिए, सेना भेज दो, हमें सेना पर यकीन है । यदि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण सेना भर भरोसा उठ जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बयान देकर आपने सेना के साथ न्याय नहीं किया है और खासकर इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि जिन्हें भी अंनतनाग की घटना का पता चला वे चौंक गए कि यह कैसे हुआ ? क्यों हुआ ? मुझे खुशी है कि वहां की सरकार ने तुरंत इसकी जांच जारी की और उस जाचं की रिपोर्ट आनी बाकी है। उससे इस प्रकार का बयान कोई प्रमुख सदस्य सदन में दे तो किसी ने सही कहा है कि इसका उपयोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान करेगा, टी.वी. करेगा । क्यों नहीं करेगा ? उसका हक है । यह फैक्ट है। मैं केवल इसकी बात नहीं करता, मैं इसके लिए रूकूंगा जब तक जांच रिपोर्ट न आए । मैंने सेना से जानकारी ली । मैनें कहा कि पाकिस्तान के लोग ह्यूमन राइट्स का सवाल उठाकर दुनिया मं हमें बदनाम करेन की कोशिश करते हैं । पिछले दस सालों में जम्मू-कश्मीर में अगर कहीं पर ज्यादती किसी सैनिक ने की, किसी पैरा-मिलीट्री फोर्स वाले ने की तो उसमें हमने क्या कार्रवाई की, इसकी मुझे रिपोर्ट दे दो । आज मैं पाता हूं कि कुल मिलाकर जितने केसिज आए, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के या किसी सैनिक द्वारा एक्सोसिज़ करने के, तो 94 सैनिकों को जेल भेजा गया अलग-अलग काल के लिए । 22 लोगों को बर्खास्त किया गया, हटाया गया । मैं नहीं जानता कि दुनिया के देश इस प्रकार की स्थिति में जिसे कि शंकर राय चौधरी ने ठीक कहा कि is a war situation. It is not an internal security but it is external security which is threatening. और ऐसी स्थिति में भी हमारे सैनिक अधिकारी, हमारी सरकारें, हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इतना काम करें उसके बाद

यदि एक घटना हो गई, जिसमें कोई एक्सेस कमिट हो गया, जिसके बारे में जांच भी बिठाई गई, उसके बाद भी यह कहा जाए तो यह बहुत शर्म की बात है। सार्वजनिक रूप से उसके बारे में हम यह बयान दें तो क्या हम इन सैनिकों के प्रति न्याय करते हैं ? मुझे लगता है कि हम न्याय नहीं करते। बहुत कठिन स्थिति में वे लोग लड़ रहें हैं। ऐसी स्थिति मे अगर कोई कसौटी है- ठीक है एक कसौटी दी जा रही है कि कितने लोग मारे गए, कितने आम लोग मारे गए, कितने मिलीटेंट्स मारे गए ? एक स्थान पर मैंनें जिक्र किया, जिक्र मैंने केवल इसलिए किया क्योंकि यह धारणा बनी है कि बांदीपुर में हमला हुआ, सिखों पर हमला हुआ और मिलीटरी इंस्टालेशन पर हमला हुआ Perhaps, the militants are having an upper hand.

और हम कुछ कर नहीं पा रहें हैं। इसलिए कारगिल के बाद अगस्त से लेकर अप्रैल तक का मैने जिक्र किया तो इसलिए कि कारगिल के बाद से लेकर इतनी मिलीटेंट्स को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेमिनैट किया, इसकी संख्या दी है। एक संख्या यह भी हो सकती है। कुल मिलाकर एक मोटा आंकडा मेरे सामने आता है और उसमें भी यदि इस प्रकार के वक्तव्य हमारे मानीनय सदस्य दें कि पचास से लेकर सत्तर हजार की संख्या होंगी, मैं सुनकर हैरान हुआ। जबकि यह फैक्ट है कि यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। सीधे युद्ध में कभी भी इतने लोग नहीं मारे जाते जितने प्रॉक्सी युद्ध में मारे गए हैं। दस हजार सिविलियन्स इन दस सालों में मारे गए हैं।

SHRI GHULAM NABI AZAD: I want to correct you. Today morning, I talked to the Director-General of Police and the Chief Minister. The figure they have given is 32,000. So, either you are wrong or the State Government is wrong.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जो बता रहा हूं मैं दस हजार सिविलियन की बात बता रहा हूं।

SHRI GHULAM NABI AZAD: About civilians, they told me that it is more than 25,000.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे पास आंकड़े हैं, मंथ वाइज है, इयर वाइज है, एक एक क्षेत्र के हैं। उनके आधार पर करीब 10 हजार सिविलियन नाइन थाउजेंड मिलिटेंट्स ऐंड टू थाउजेंड सेक्युरिटी मैन थे। मैं मानता हूं कि ...

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी: बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बहुत नुकसान हो रहा है। यह छोटा अमाउंट नहीं है। यह बहुत बड़ी फिगर है। लेकिन अगर कसौटी पर लेना है तो बहुत सही बात हमारे गुलाम

नबी आजाद जी ने कहा कि वहां पर उद्योग नहीं है । जम्मू-कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं है अगर कोई इंडस्ट्री है तो वह टूरिज्म है और टूरिस्ट का जो इन्फ्लेक्स होता है उसको मैं ज्यादा सही कसौटी मानता हूं । मैं अभी अभी जम्मू-कश्मीर गया था । वहां पर जितने लोग मिले वे एक ही बात कहते थे कि आडवाणी साहब टूरिस्ट भेजिए । चाहे नाव वाला हो, शिकार वाला हो, दुकानदार हो वे एक ही बात कहतें हैं, मैं सारी वेली की बात कर रहा हूं, केवल श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूं कि टूरिस्ट भेजिए । सारा उद्योग इस पर अवलंबित हैं । इसमें मैं देखता हूं कि जिस काल की बात आपने की है उस काल से अब स्थिति अच्छी हो गई है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : दूसरा मैने बताया था कि 30-32 हजार । मैंने यह अलग अलग नहीं कहा । मैने लोगों को अलग अलग नहीं किया । डिफेंस और फोर्स के लोगों को अलग नहीं किया और कहा कि कुल इतने लोग मरे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैने आपको ऐक्चुअल फिगर दी है । आपने उस समय 50 हजार, 70 हजार कहा। आपकी बात रिकार्ड में है । उस समय सदन के नेता बैठे थे, उन्होनें मुझे कहा कि देखिए इस बात को लोग कोट करेंगे कि 50 हजार है, 70 हजार हैं ।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसमें सेक्युरिटी फोर्सेज भी हैं ।

***श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफ** : इसी बात को प्रेस के जरिए से आम बात बनायी जा रही है कि 70 हजार के करीब लोग मारे गए हैं । जो न मिलिटेंट हैं और न फोर्स के लोग हैं । ऐसा कहा जा रहा है । तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि आप स्टेट गवन्नमेंट से कहकर बाकायदा सर्वे कराकर इनकी पूरी लिस्ट साया कर दें ताकि लोगों को पता चलें की हकीकत क्या है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैनें कहा है कि हम नार्मलसी की ओर कितना जा रहें हैं । वहां पर टूरिज्म कितना पनप रहा है, टूरिस्ट ट्रैफिक कितना है और इसको मैं कसौटी मानता हूं । मेरे पास आंकड़े हैं और जब मैं उन्हें देखता हूं तो पाता हूं कि In 1995, the tourist traffic of domestic tourists in the Kashmir Valley went down to an all-time low of 322 in the whole year, पूरे साल में 322 यात्री भारत के कश्मीर वैली में गए । 1989 से लेकर जो ड्राइंग अप शुरू हुआ और 1995 में यह काम होते होते 322 हो गया और फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और 1996 में यह 375 हुआ । पहली बार 1998 में पूर्व स्थिति की और जाने के लक्षण मिले क्योंकि पूर्व स्थिति लाखों में होती थी । इस स्थिति

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

की ओर जाने के लक्षण 1998 में मिले जब टूरिस्ट 99636 हुआ और जो पिछले दो सालों से बराबर आगे बढ़ता जा रहा है । यद्यपि 1999 में कारगिल बीच में आ गया और कारगिल के बीच में आने के कारण वहां मामला रूक गया । मैं मानता हूं कि प्राक्सी वार में पाकिस्तान को जो पराजय मिली है वह कारगिल का एक फैक्टर है । कारगिल की पराजय ने पाकिस्तान को फिर से प्राक्सी वार के लिए उत्तेजित कर दिया,प्रेरित कर दिया । ये दोनों इंटररिलेटेड हैं । हमें इस सच्चाई को पहचानना चाहिए । इस सच्चाई को पहचानने के बाद यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान सफल नहीं हुआ है। वह इन दो सालों में विफल हुआ हैऔर वह प्राक्सी वार में भी विफल होगा इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । अभी अभी मैं वहां से होकर आया हूं । यह ठीक है कि जिस समय कारगिल युद्ध आया मैने उसका थोडा सा जिक्र अपने वक्तव्य में किया है । कारगिल के युद्ध के समय हमारे पास कोई आप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि सेना जो सिक्योरिटी ग्रिड में लगी हुई थी, इंटर्नल सिक्युरिटी में लगी हुई थी, डोडा. पुंछ, राजोरी और कश्मीर वैली में लगी हुई थी, उन सब को वहां से हटा कर के कहा कि जाओ कारगिल में जा कर उनको रोको, उनको पराजित करो, कारगिल में जहां उन्होनें कब्जा किया है,वहां से उखाड़ कर बाहर फैंकों । उसमें उन्होनें बहादुरी दिखाई, उन्होनें जो साहस दिखाया, उसके कारण हम कारगिल का युद्ध जीते, विजयी हुए । कारगिल के युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई, वह पूर्व की विजय से इस नाते से बिल्कुल भिन्न है कि पहले हम 1947 में जीते, 1965 में जीते, 1971 में जीते, तीन बार जीतने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह धारणा हमेशा बनी रही कि हमने कोई ठीक नहीं किया, भारत ने ठीक नहीं किया, इस मामले में पाकिस्तान ज्यादा ठीक है । यह पहला युद्ध था 1999 का जिसमें भारत को दोहरी विजय प्राप्त हुई, रणभूमि की विजय और कूटनीतिक विजय आनॅ दी बैटल फील्ड...(**व्यवधान**)...

श्री मूल चंद मीणा :पहले उनको भीतर घुसाया और फिर बाहर निकाला ...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह देश की विजय है, इसको कोई सरकार की विजय नहीं मानते ।...(**व्यवधान**)... सैनिकों को हम क्रेडित देते हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री मूल चंद मीणा: गलती किस की रही ? ...(**व्यवधान**)... उनको घुसने किसने दिया था ? ...(**व्यवधान**)...

DR. KARAN SINGH (Delhi): Mr. Chairman, Sir, I want to submit one point. I do not think it is correct to devalue or underrate our tremendous victory in the Bangladesh war. ... *(Interruptions)*...

SHRI L.K. ADVANI I am not underrating. ...*(Interruptions)*...

DR. KARAN SINGH ; My submission, Mr. Chairman, Sir, is that both are entirely different problems. You cannot ...*(Interruptions)*... Advanji, I will take only one minute. That was not only a great military victory, but it was also accepted around the world as a tremendous new diplomatic victory because a new nation was created out of this victory. So, I would submit that this is an entirely different matter. That was a national victory. It is a different thing. ...*(Interruptions)*... It is not befitting that you should devalue one for the other.

SHRI L.K. ADVANI : So far as Dr. Karan Singh is concerned ... *(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE It was equally a diplomatic victory; a new nation was born. Please clarify that point. A new nation was created which was recognised by every country. Immediately after that, a new recognition came. How can you say that it was a diplomatic failure? You cannot say that it was a diplomatic failure. It is a national success; it was an international success. ... *(Interruptions)..'*. I take strong exception to the statement that the victory of 1971 was not an international victory. It is wrong on the part of the Home Minister to make such a statement. He cannot do that. ...*(Interruptions)*... Please clarify that point. ... *(Interruptions)*...

श्री रामचन्द्र खूंटिया(उड़ीसा): वह दूसरी तरह की लड़ाई थी ...(**व्यवधान**)... इसको कंपेरिजन कैसे कर सकते है आप ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आजाद : अपने घर को खाली करवाने को जीत मानते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : यह तो अपनी जगह खाली करवाई है ...(**व्यवधान**)... आपने गलत कहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : क्या गलत कहा है ? ...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापमि महोदय, 1971 के युद्ध की तो इतनी शानदार विजय थी उसके कारण पाकिस्तान को सोचना पड़ा कि हम इनके साथ युद्ध में मुकाबला कर ही नहीं सकते। इनके साथ मुकाबला करने गये जैसे चौबे जी छब्बे बनने गये और दुबे रह गये। There was no question of comparing. That was a spectacular victory, हमारे उस समय के नेता वाजपेयी जी जो उस समय भारतीय

जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होनें जिस प्रकार से उस समय की सरकार और सरकारी के प्रधानमंत्री की जिन शब्दों में उसकी प्रशंसा की, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती । लेकिन हां, हम इस बात को भूल नहीं सकते कि अमरीका ने सेवन्थ फ्लीट भेजा था उस समय हमको पराजित करने के लिए । मैं तो यह कह रहा हूं कि इस बार की विक्ट्री में यह जुड़ गया कि विश्व भर ने पहचाना कि कश्मीर के मामले में कारगिल के मामले में भारत सही है और इसीलिए उस समय अमेरिका ने सेवन्थ फ्लीट भेजा था यहां पर हमारे खिलाफ । इस बात को हम भूल नहीं सकते । यह सोचना कि हमने 1971 में ...(**व्यवधान**)... । am not vielding.

SHRI GHULAM NABI AZAD: We should not forget that, at that time, the world was a bi-polar world, but, today, it is a uni-polar world..... *(Interruptions)* ...

श्री संघ प्रिय गौतम : इनको बैठाइए ...(**व्यवधान**)... किसी को नहीं बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI T. N. CHATURVEDI: Let the Leader of the Opposition speak. Why is Mr. Ghulam Nabi Azad interrupting? We will not allow that. ....*(Interruptions)* ...

LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): We are having a very serious debate on the security environment and the grave situation prevailing in Jammu and Kashmir. I do believe that nothing should be done to detract from the seriousness which this House attaches to the grave situation prevailing in Jammu and Kashmir. Therefore, I beg of the hon. Home Minister not to indulge in polemics which would give an indication to the rest of the world that in dealing with this grave situation, we are not of one voice. I respectfully request the hon. Home Minister not to insist on describing the 1971 event and the 1999 event ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJU PARMAR: What is this? The Leader of the Opposition is speaking ....*(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN: Let the Leader of the Opposition complete it. *(Interruptions)* ...

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, I once again request the hon. Home Minister not to make these comparisons. He has seen, for

example, that we do not agree with the way in which he has described the event of 1971 tod the way in which he has compared the event of 1971 with that of 1999. I think, by indulging in this polemics, he is detracting from the seriousness which all segments of this House attach to the situation in Jammu and Kashmir. If the hon. Home Minister is not withdrawing those words, I think, we will not be a party to this.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: He should withdraw his words about the 1971 war. Otherwise, we are not going to participate in this. You cannot compare this with the Bangladesh war.

SHRI S. S. AHLUWALIA: What is there to be withdrawn? Why should he withdraw it?

SHRI L. K ADVANI: I have not compared anything. ... *(Interruptions)....*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You should withdraw those words.

SHRI L. K ADVANI: I have said that the victory of 1971 was a historic victory. It is a triumph, for which there is no parallel. But, so far as the world opinion about India-Pakistan relations in the context of Kashmir, is concerned, for the first time, there was a change this time. There is nothing else.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is your individual assessment. I do not agree with that assessment.

SHRI L. K. ADVANI: You may not agree with it. I do not expect you to agree with it. But, at the same time, I say कि उसमें परिवर्तन आया । एटीटयूड में परिर्वतन आया और वह एटीट्यूड में परिवर्तन जो है आज निश्चित रूप से है । आज हम जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार की समस्या का सामना कर रहें हैं उसमें हमारी टू-प्रांग्ड एप्रोच है । एक तरफ तो हम जमीन पर इन उग्रवादियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के माध्यम से मुकाबला कर रहें हैं वहां, दूसरी ओर विश्व भर में इस बात की कोशिश कर रहें हैं कि जो भी राज्य क्रास बार्डर टेरोरिज्म की अपनी पालिसी अपनाकर पडोसी देश पर हमला करें तो उसके खिलाफ विश्व भर में वातावराण बने । मैं मानता हूं कि उस विश्व भर में वातावरण बनाने में हमने कारगिल में जिस प्रकार से युद्ध का संचालन किया उसने बहुत बड़ी सहायता की । कुछ लोग मजाक उडाते हैं श्री वाजपेयी जी का आप लाहोर क्यों गए आपको नहीं जाना चाहिए था । मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर विश्व भर में जो परिवर्तन हो रहा

है ...। टूवड्र्ज क्रॉस बॉर्डर टैरोरिज्म उसमें से भारत के प्रधान मंत्री का स्वंय लाहौर जा करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना, वह एक प्रकार से बहुत बड़ी भूमिका है ।

DR. MANMOHAN SINGH Sir, I do not want to detract from the achievements of the country, whether it is in Kargil or in Bangladesh. I would respectfully request, once again, the hon. Home Minister, to withdraw those words that he said, that the 1971 war was a diplomatic defeat. If you do not, we will walk out. *(Interruptions).* We walk out.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Mr. Home Minister, when we are discussing questions which are relevant today, you were degrading the discussion by your statement. *(Interruptions).* We are sorry to say that. You are taking unnecessary issues, out of bounds. We also walk out in protest against your statement.

SHRI R. MARGABANDU: We also walk out. *(Interruptions).*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: This is your election politics. *(Interruptions).* We too walk out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): They have given wrong figures. They have misled the nation. They have misled the whole House also.

SHRI ADHIK SHIRODKAR: I have been finding regularly that points are made not because of the concern about issues, but to take political mileage. When that political mileage is negatived by good reasoning, by good facts, the only way for them is to stage a walk-out. I think this is a wrong practice. *(Interruptions).*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : When they speak, we keep quiet, we hear them. They complete their speeches. At the end of it, they make some allegations and then walk out. Should we only keep quiet in this House on such sensitive issues, national issues? They are only trying to score political points.The entire country is watching us. People say, "You verify the record". They say 60,000 people died, 40,000 people died. 35?t ^ 31TOI, *fibii*^ f^JT I Is this not an insult to the country? Are we not harming the interests of the country? Is this the behaviour of responsible parties or Members of Parliament? We should keep the country's interest in mind. He

has not uttered any word. They are asking him to withdraw the words that he has used. Please go through the record. There is no mention about that particular thing.

SHRI SR. BOMMAI (Karnataka): Nobody disputes the high standards of the debate. But, walk-out is a method democratically exercised by the Opposition whenever it disagrees with the Government or whenever they do not get a proper reply from the Government. I was not present. So, I do not want to comment about the statement of the Home Minister. But Mr. Venkaiah Naidu has no right to comment on the conduct of the Members when they walk out.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: As a Member, I have got a right to express my opinion. Do you want to curtail that?

SHRI T.N. CHATURVEDI: We listen to them patiently. They should also listen to us patiently. Then they can leave. We do not dispute their right.

SHRI S.R. BOMMAI: On this side, the present hon. Home Minister and we, together, a number of times, have walked out.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There is nothing wrong in a walk-out. But hear others also.

SHRI T.N. CHATURVEDI: It is good for health to walk. But there is a time for it.

SHRI SHARIEF-UD-DIN SHARIQ: There is a difference between a walk-out and a run-out.

सर, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कश्मीर के बारे में बात हो रही थी.कश्मीर की मुश्किलात के बारे में बात हो रही थी, मुसलमानों के बारे में बात हो रही थी, कश्मीर और देश के ताल्लुक को मजबूत बनाने की बात हो रही थी । इस आधार पर मामूली बात का बहाना बनाकर ये लोग बाहर चले गए । या तो उन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है । अगर है तो वे शर्मिन्दा है और खिसियानी बिल्ली की तरह भाग रहे हैं ।

मुझे ईमानदारी के साथ कहने दीजिए चाहे बाद में होम मिनिस्टर साहब मुझे हथकड़ियां भी पहनांए । लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 1971 की जंग ने उन के साथ जो बिना वजह लड़ी और वाह-वाही मिली, इस वजह से भी यह दुश्मनी गहरी बनी और उसी का

नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं । तो लिहाजा मैं बहुत जरूरी चीज के खिलाफ एहतजाज करता हूं कि कश्मीर के बारे में इतनी नफरत क्यों हैं इन के दिलों में ? उन को बैठाना चाहिए था, सुनना चाहिए था और होम मिनिस्टर साहब से क्लिअर जवाब लेना चाहिए था और वह वहां क्या करने जा रहे हैं बेहबूदी के लिए, वह लेना चाहिए था । महज अब गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वाक-आउट करना, यह भी कोई सियासत हो सकती है ?

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): सर, एक इजाजत दें । आप यहां मौजूद है, कौन सी ऐसी बात कही गयी जिस के लिए उन्होनें विद्ड्रा करने की चर्चा की ?

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : सर, मामला कुल इतना है कि हम लोग यहां बैठे सुन रहें हैं । होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान हम से 1948 से लेकर अब तक लड़ता हुआ आ रहा है । हम ने 1948 में भी उस को पराजय दी, 1965 में भी उस को पराजय दी,1971 में भी पराजय दी और कारगिल में भी उस को पराजय दी । मगर कारगिल की पराजय कुछ अलग ढंग से पराजय थी । उस पराजय में हम इतना बड़ा मैसेज नहीं दे पाए जितना बड़ा मैसेज इस वक्त हम ने दिया । हम ने कूटनीति में भी उन को पराजित किया और बॉर्डर पर भी उन को पराजित किया । सर, अब मामला यहां से आया कि 1971 की जंग का हवाला आप मत दीजिए इसलिए कि 1971 की जंग एक ऐसी जंग हुई जिसमें एक देश के दो टुकड़े हुए । पाकिस्तान की कोख से अलग होकर बांग्लादेश बना और हम ने हिंदुस्तान की गर्वनमेंट ने अपनी राजनीति से पूरी दुनिया के जरिए बांग्लादेश को मान्यता दिलवा दी और हम ने कारगिल से बड़ा एक मैसेज दिया था । इसलिए आप यह पॉलिटिकल फतह हासिल करने की कोशिश मत कीजिए । मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल वे में जाकर दोनों साइड ने अपनी-अपनी बात को रखा है वरना सच्ची बात यह है कि हम 1971 में भी हिस्टोरिकल जंग जीते थे और कारगिल में भी हम हिस्टोरिकल जंग जीते हैं । इस पर और अच्छे ढंग से गुफ्तुगू कर के कश्मीर कर के कश्मीर के मसले को मुल्क की कौमियत और इत्तेहाद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था ।

SHRI P.N. SIVA (Tamil Nadu): Sir ...

MR. CHAIRMAN: Let the Home Minister reply.

SHRI P.N. SIVA: Sir, I have to say only one thing. We were discussing a very grave and important issue on which they have expressed their views and the Home Minister is giving reply to those points. What they have done is not a good thing. It will send a wrong signal to the nation and to the people all over the world that we are not having a consensus on

this issue. So, this type of attitude to gain political mileage by asking the Home Minister to withdraw something which he has not said, is not fair. We must arrive at a solution to this problem. We must try our best to solve this problem to mitigate the sufferings of the people in the Valley. It is our duty to bring to the notice of the Chair that what they have been repeatedly doing in the House is not a healthy practice. Thank you.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, दो साल से इस सरकार के सामने आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से समस्याएं आ रही है । केवल जम्मू-कश्मीर में नहीं, उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी ये रही है । सभापति जी, जिन तीन चीजों का उल्लेख हम ने इस में किया है कि हमारा त्रि-सूत्रीय एप्रोच है, पॉलिसी है, उस में पहला यह है कि जो लोग हिंसा, आतंकवाद के सहारे देश को कमजोर करना चाहते हैं, उन को सेक्युरिटी फोर्सेस के माध्यम से निरस्त करना और विफल करना । लेकिन उस के साथ-साथ हम यह जानते है कि चाहे पाकिस्तान के आई.एस.आई. ने या पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने काम किया हो, अगर लोगों को रोजगार हो, लोग खुशहाल हों तो वे उस के चक्कर में नहीं फसेंगे । लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जैसी कि शरीफ-उद्-दीन साहब ने बताई कि लोगों के पास रोजगार नहीं है और उन्हें कोई आकर कहता है कि तुम को यह रोजगार मिल जाएगा, तुम को 5 हजार रूपए मिल जाएंगे, तुम्हारे घर में जो कमी है या जो विवाह होना है यह कर देंगे तो वह फिसल जाता है और वह गलती कर डालता है । वही चीज उत्तर-पूर्व में हुई । और इसलिए वहां पर चाहे नागालैंड हो, चाहे बोडोज़ हों, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ जब उन्होनें भी माना कि अच्छा हम बातचीत करने को तैयार है । इन दिनों में खासकर के कारगिल के बाद, मैंने कारगिल का ज़िक्र वैसे ही नहीं किया, बहुत सोचकर के किया कि कारगिल के बाद ऐसी स्थिति आई जब कि पाकिस्तान ने अपनी प्रॉक्सी वार बढ़ा दी, उसको और अग्र बना दिया और हमारे मिलिट्री-आर्मी इंस्टालेशंस पर भी हमला शुरू कर दिया और सुसाइड स्कवेड भेजकर के एक मोटरकार में अपने एक्सप्लोसिव्स रखकर ये सारे काम किए, तो सरकार से पहले तो हम हमेशा कहते थे कि हम बातचीत करने को तैयार है, आप किसी भी विषय पर बातचीत करिए, आप कश्मीर पर बातचीत करें, हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन कारगिल के बाद और खासकर के प्राक्सी वार के ऐग्रावेशन के बाद एक सुविचारित फैसला किया गया कि हम पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो अपना यह रवैया नहीं छोड़ता । मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया के देशों ने भी, जो लोग पहले हमको बार-बार कहते थे कि बात करो, बात करो, उन्होनें भी कहना शुरू किया कि हां, बातचीत के लिए पाकिस्तान को ही ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सार्थक बातचीत हो सके । यह दृष्टिकोण आने के

बाद हमको लगा कि जम्मू-कश्मीर में भी कुछ लोग है जो हमारी नीतियों से नाराज़ हैं, जो कोई कारणों से जेल में बंद हैं, यह मौका है कि हम उनको छोड दें । यह नहीं कि हम कोई बात कर रहें हैं इसलिए उनको छोड़ रहें हैं, यह मौका है कि हम उनको छोड़ देते हैं, वे बातचीत करना चाहे तो करें । मैनें केवल एक वाक्य का उल्लेख किया इसमें क्योंकि आपने उसको तो थर्ड कहा, शायद हमारे सी.पी.एम. के नेता ने जिक्र किया कि "So far as the third part of the strategy is concerned, you have made only one statement; you have said one single sentence only." It is true क्योंकि अभी तक हमने तय यह किया है कि फलां का यह बयान आया है, फलां का यह बयान आया है, आपका क्या कहना है । कश्मीर स्टडी ग्रुप का यह है, आपका क्या कहना है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस समय मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, जो कुछ कहा है इस वक्तव्य में कहा कि बातचीत करेंगे तो संविधान के दायरे में करेंगे और संविधान के दायरे में कोई भी हमारा हिस्सा, हमारे संविधान का हिस्सा किसी दूसरे को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता । इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने सारी बातें की है । जम्मू-कश्मीर के उग्रवाद का मुकाबला करने में एक-एक कदम सोच-विचार कर सरकार ले रही है । हम सबको सलाह कर रहें हैं, पार्लियामेंट के कई मैम्बर मुझसे मिलते रहें हैं । अगर यह सुझाव है कि मैं दस लोगों से एक साथ मिलूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, आल पार्टी मीटिंग बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका कोई अवसर होना चाहिए । और सरकार आएगा तो सरकार निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलेगी ।

मुझे विश्वास है कि जहां पंजाब में कुछ साल पहले ऐसी स्थिति दिखती थी कि शायद वहां नार्मेल्सी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी, आज शायद किसी को लगता हो कि जम्मू-कश्मीर में भी वैसी ही है, वैसा है नहीं । आज भी वहां जाकर देखिए तो नॉर्मल काम चल रहा है । एक आध बड़ी घटना हो जाती है चट्टीसिंह पुरा जैसी तो सारे देश में तहलता मच जाता है, वह करना बहुत मुश्किल नहीं होता है लेकिन सामान्यतः वहां पर गतिविधि नॉर्मल है, बहुत अच्छी चल रही है और मैं समझता हूं कि देश निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने कारगिल में उनको पराजित किया, इस प्राक्सी वार में भी देश उकनो निश्चित रूप से पराजित करेगा।

THE NATIONAL HOUSING BANK (AMENDMENT) BILL, 2000

MR. CHAIRMANiHon. Members, we will now take up the